सत्र-04(भाग-2) 23मार्च, 2026

खण्ड- 08 .... सोमवार, ...

अंक- 23 02 चैत्र,1948(शक्)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

आठवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08 सत्र-04(भाग-2) में अंक 23 से 26 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विभान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-04(भाग-2) सोमवार, 23मार्च,2026/02 चैत्र,1948(शक्)अंक-23

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4-5
2.	निधन संबंधी उल्लेख	7-8
3.	बधाई प्रस्ताव(नियम-114)	9-17
4.	विशेष उल्लेख(नियम-280)	18-25
5.	वित्तीय समितियों का निर्वाचन	26
6.	समितियों के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण	27-35
7.	माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य	36-37
8.	माननीय मंत्री का वक्तव्य(नियम-270)	38-48
9.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	49-52

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-04(भाग-2) सोमवार, 23मार्च,2026/02 चैत्र,1948(शक्)अंक-23

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

दिनांक 23.03.2026 को सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्य का नाम	क्र.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अहिर दीपक चौधरी	26.	श्री पंकज कुमार सिंह
2.	श्री अभय कुमार वर्मा	27.	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत
3.	श्री अजय कुमार महावर	28.	श्री प्रवेश साहिब सिंह
4.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	29.	श्रीमती पूनम शर्मा
5.	श्री आशीष सूद	30.	श्री राज करन खत्री
6.	श्री अशोक गोयल	31.	श्री राज कुमार भाटिया
7.	श्री चन्दन कुमार चौधरी	32.	श्री राज कुमार चौहान
8.	डॉ. अनिल गोयल	33.	श्री रवि कान्त
9.	श्री गजेन्द्र दराल	34.	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह
10.	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	35.	श्री रविन्दर सिंह नेगी
11.	श्री हरीश खुराना	36.	श्रीमती रेखा गुप्ता
12.	श्री जितेन्द्र महाजन	37.	श्री संदीप सहरावत
13.	श्री कैलाश गहलोत	38.	श्री संजय गोयल
14.	श्री कैलाश गंगवाल	39.	श्री सतीश उपाध्याय
15.	श्री कपिल मिश्रा	40.	श्रीमती शिखा रॉय
16.	श्री करनैल सिंह	41.	श्री श्याम शर्मा
17.	श्री करतार सिंह तंवर	42.	श्री सूर्य प्रकाश खत्री
18.	श्री कुलदीप सोलंकी	43.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह

19.	श्री कुलवन्त राणा	44.	श्री तिलक राम गुप्ता
20.	श्री मनजिंदर सिंह सिरसा	45.	श्री उमंग बजाज
21.	श्री मनोज कुमार शौकीन	46.	श्री विजेन्द्र गुप्ता
22.	श्री मोहन सिंह बिष्ट		
23.	श्रीमती नीलम पहलवान		
24.	श्री नीरज बैसोया		
25.	श्री ओम प्रकाश शर्मा		

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र 04 सोमवार, 23 मार्च,2026/02 चैत्र 1948 (शक)अंक-23

सदन पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:वंदे मातरम लाईव होगा आज।

(राष्ट्रीय गीत- वंदेमातरम)

भारत माता की जय

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण, आज आठवीं विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में हमेशा की तरह हमें लोकतांत्रिक दायित्वों के निर्वहन, जनहित के मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श तथा नीतिगत निर्णयों पर चर्चा के लिए अवसर मिलेंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता पूर्वक अपने विचार सदन में प्रस्तुत करें और सदन का समय खराब ना होने दें। साथ ही कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय को मेरी अनुमति के बिना ना उठाएं। यह बजट सत्र है और बजट पर चर्चा के दौरान आपको विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र के दौरान सभी माननीय सदस्य लोकतांत्रिक मर्यादाओं, संसदीय परंपराओं और उच्च आदर्शों का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही की गरिमा को बनाए रखेंगे। यह सदन दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतीक है। अतः हम सभी का यह दायित्व है कि हम उन आशाओं पर खरे उतरें और विकास, सुशासन तथा समावेशी प्रगति की दिशा में ठोस कदम उठाएं। मैं सभी माननीय सदस्यों को इस सत्र के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह सत्र सार्थक, सफल और सकारात्मक सिद्ध होगा।

शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, आज 23 मार्च है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का बहुत पावन और गौरवशाली दिन है। आज ही के दिन अमर क्रांतिकारियों शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इन महान विभूतियों का साहस, त्याग और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इन अमर वीरों ने अपनी देशभक्ति से पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार किया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि देश हित सर्वोपरि है और इसके लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से सभी अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे उनके आदर्शों को अपनाकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए लगातार अपना योगदान देते रहें।

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय सदस्यगण, यह बहुत दुख का विषय है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार का गत 28 जनवरी, 2026 को एक विमान दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया। यह दुर्घटना मुंबई से बारामती जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई जिसमें उनके साथ चार अन्य व्यक्तियों का भी निधन हो गया। श्री अजीत पवार एक अनुभवी, कर्मठ और जनप्रिय नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास तथा जन कल्याण के लिए लंबे समय तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से ना केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिजनों तथा उनके समर्थकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिजनों तथा उनके समर्थकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण दिनांक 18 मार्च, 2026 को पालम क्षेत्र में एक बहु मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई। जिनमें तीन मासूम बच्चे भी शामिल थे और

तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुखद घटना पर मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें। साथ ही मैं इस घटना में घायल हुए सभी व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं तथा आशा करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का और अधिक सुदृढ किया जाएगा। अब शहीदों के सम्मान में और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जाएगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया)

ओम शांति।

माननीय सदस्यगण, आपको आप सबको विदित है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने 8 मार्च, 2026 को अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह जीत भारतीय क्रिकेट टीम के उत्साह, अनुशासन, परिश्रम और संकल्प का प्रतीक है। खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम भावना, धैर्य और खेल कौशल का परिचय देते हुए विश्व के मंच पर भारत का परचम लहराया है। इतनी बड़ी उपलब्धि पर मैं सदन की ओर से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उनकी यह सफलता देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश देती है। हम आशा करते हैं कि भारतीय टीम भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करके देश का मान बढ़ाती रहेगी।

माननीय सदस्य गण मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सदन की कार्यवाही को अधिक प्रभावी शोधप्रद तथा तथ्य आधारित बनाने और सदस्यों की सहायता के लिए एक नई पहल की गई है और दिल्ली विधानसभा ने अपना विधान साथी एआई चैट बॉट विकसित किया है। आप सभी माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए इस चैट बॉट का क्यूआर कोड आपकी टेबल पर उपलब्ध कराया गया है। जहां आपकी शीट है ऊपर है यह। इसे स्कैन करके आप इसके लिंक पर जाकर आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्लेटफार्म के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों पर तुरंत विश्वसनीय रिसर्च सपोर्ट मिलेगा। जिससे आपकी चर्चाएं अधिक तथ्यप्रद और डाटा एंड ओरिएंटेड डाटा ओरिएंटेड बन सकेंगी। यह सुविधा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही इसे वॉइस कमांड के माध्यम से भी प्रयोग किया जा सकता है। यह विशेष सुविधा केवल माननीय इस विधान सभा सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित की गई है। मैं आशा करता हूं कि आप इस तकनीकी पहल का अधिकतम उपयोग कर सदन की कार्यवाही को और अधिक

प्रभावी और सार्थक बनाएंगे। यह जो चैट बॉट है इसका जो लिंक है वह भी आपको शेयर कर दिया गया कर दिया जाएगा। आप सदन के बाहर भी अपने निवास पर भी इसके माध्यम से मदद से अपनी स्पीच तैयार कर सकते हैं। डाटा कर सकते हैं। जो एजेंडा सदन में पेश होता है वो कई बार बहुत हैवी होता है। 100 पेज का मान लीजिए आइटम है। तो उसको आप अगर समराइज करा के उसके कुछ पॉइंटर्स में उसकी समरी अगर आप चाहते हैं वो भी इससे आपको मिलेगी । जिसे आपको बातचीत में आसानी भी होगी और सार्वगर्वित आपकी बातचीत होगी। मैं चाहूंगा कि इसका एक डेढ मिनट का एक डिस्प्ले है जिससे आपको और इस बारे में स्पष्टता आयेगी। उसको दिखाया जाये ।

(विधान साथी एआई चैट बॉट पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई)।

माननीय सदस्यगण अब निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे।

श्री आशीष सूद (माननीय गृह एंव शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी मैं एक विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपकी अनुमति चाहता हूं। देश में कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द स्टेट के नाते सबसे ज्यादा दिन पूरे किए और संजोग है। कल उसके पूरा होते ही आज सदन का एक हाउस चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सदन माननीय प्रधानमंत्री जी का इस विशिष्ट उपलब्धि पर एक बार संज्ञान लेते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हुए उनको बधाई दे। ऐसी अनुमति मैं आपसे चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने जो विषय यहां रखा है निसंदेह कि वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि सर्वोच्च पद पर रहते हुए किस प्रकार उन्होंने एक संत के रूप में देश की सेवा की है और एक बेदाग जीवन एक विकास और देश की तरक्की से जुडा हुआ जीवन उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। तो चाहूंगा इस पर आप ही कुछ कहना शुरू करें। प्रस्ताव रखें।

<u>बधाई प्रस्ताव(नियम-114)</u>

श्री आशीष सूद (माननीय गृह एवं शिक्षा मंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत-बहुत आभार। कल देश ने एक विशिष्ट दिन को देखा है। जिसमें यहां बैठे अनेक लोग उस सफर में किसी ना किसी रूप में अनुयायी के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2001 से लगातार कल 8931 दिन पूरे करते हुए हेड ऑफ द स्टेट के नाते बिना

एक भी दिन के ब्रेक के बिना एक भी दिन के ब्रेक के देश में सबसे ज्यादा हेड ऑफ द स्टेट मुख्य मंत्री और फिर लगातार प्रधानमंत्री के रूप में एक उपलब्धि ली है और यह उपलब्धि उन्होंने केवल हेड ऑफ द स्टेट के नाते नहीं ली है। एक जैसा आपने शब्द का इस्तेमाल किया संत के रूप में। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने लोक सेवा में सत्ता में रहते हुए लोक सेवा में सत्ता को साधन नहीं साध्य मानते हुए जनता की सेवा करने के लिए नए पैमाने दिल्ली अनेक रूपों से उनके इस विशिष्ट प्रयासों से लाभान्वित हुई है। उनसे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता के बीच में जाने का काम अभी हाल ही में एक वर्ष पूरा होने में उनकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हजारों बच्चियों के जो बच्चियों के नाम पर उनके अकाउंट के पैसे थे पिछली सरकारों ने बिल्कुल लापरवाही से वो पैसा सरकार के बैंकों के सस्पेंस अकाउंट्स में पड़ा था। ऐसी अनेक प्रेरणादायक पहल प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में हुई है जिससे प्रेरणा लेकर ये सरकार भी काम कर रही है और यहां बैठे सभी साथी उन्हीं की प्रेरणा से जनसेवा के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से जनसेवा के नए आयाम हम स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि उनका सत्ता में रहना सत्ता के लिए नहीं है। नए-नए तरीके से, नए-नए प्रयासों से उसको स्थापित करने का काम किया गया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं सदन के समक्ष उनको बधाई देने के इस प्रस्ताव को आप सभी के समक्ष रखता हूं। आपने मुझे अवसर दिया मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: इस विषय पे अगर कोई और सदस्य भी अपनी बात कहना चाहता है उसको भी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय मंत्री: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो बधाई देता हूं देश के सभी देशवासियों को ये एक ऐतिहासिक पल है और ये जब हम कहते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग तो एक सबसे बड़ा जो इसमें अंतर है जहां देश के प्रधानमंत्री जी ने 2001 से लगातार जैसे अभी आशीष जी ने कहा बिना सांस छुट्टी लिए बिना एक दिन का भी, लगातार निरंतर देश की सेवा की। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आए। एक चाय वाला अपने देश का प्रधानमंत्री बनकर इस देश की महान सेवा कर सका हो। ऐसा असंभव था इस देश में क्योंकि इस देश में एक परिवारवाद के नाम से राज किया जाता था। इस देश के अंदर परिवार की बात की जाती है। परिवार

की भाषा परिभाषा को सीमित करके उसी के ऊपर राजसत्ता की बात करी जाती थी। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस वक्त में बेदाग होकर अपना सेवा निभाई है वो वो वक्त है जब आज के डेट में सोशल मीडिया जैसी और मीडिया जैसी ऐसी अनेकों चीजें हैं जो दिनभर आपके कार्यक्रम कार्यकाल के दौरान हुई कामों की चर्चा करती हैं। पुराने जितने भी लोग हैं वो उस वक्त हुए जब टीवी चैनल भी सरकारी थे, अखबारें भी इसी तरह चलती थी। लेकिन आज जब आपके हर काम का विश्लेषण किया जा रहा हो, ऐसे में भी उनका खरा उतरना और बेदाग छवि के साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग एक सेवा के रूप में, एक चौकीदार के रूप में उन्होंने सेवा करने का काम किया है जिसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री और देश के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब 280, आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं ना सतीश जी, पहले आप बोल लीजिए फिर आप बोल लीजिए। एक एक लाइन में।

श्री सतीश उपाध्याय: धन्यवाद अध्यक्ष जी। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प से सिद्धि की जो यात्रा अद्भुत यात्रा प्रधानमंत्री जी ने तय की है। 8931 दिन एक रिकॉर्ड तोड़कर के जिस प्रकार से एक भारत को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प के साथ हम सबको याद है कि जिस दिन वो संसद में आए थे और संसद में आकर उन्होंने संसद की सीढ़ियों में नमन किया था, उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है और उसी सरकार के संकल्प से सिद्धि के माध्यम से आज जिस तरह से पूरे भारत में विकसित भारत का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो रहा है और उसी उद्देश्यों को लेकर के हमारे दिल्ली की सरकार भी एक वर्ष के अंदर दिल्ली की सरकार ने दिल्ली कोविकसित बनाने का प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो संकल्प पूरा किया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवंत राणा: अध्यक्ष महोदय मैं भी सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं उनके सफल कार्यकाल के लिए और रिकॉर्ड कार्यकाल है हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में उनका और उनका कार्यकाल बहुत बेहतर कार्यकाल चल रहा है। एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बाद भारतीय जनता पार्टी में काम किया और सीधा मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो देश के ऐसे पहले नेता हैं जो बिना विधायक के सीधा मुख्यमंत्री बने थे और सरकार भाजपा की थी

वहां और मापदंडों के साथ काम किया और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं। एक एहसास कि पहले मैं एक राज्य का मुखिया हूं, उस संवेदनशीलता के साथ, उस वोट का एहसास समझते हुए उस प्यार का, उस समर्थन का आशीर्वाद को एहसास करते हुए और बहुत अच्छे से डिलीवर किया और जो गुजरात के अंदर डिलीवर किया उसके बाद पूरे देश ने उसको देखा और देश ने जब उसको देखा कि बहुत अच्छे से डिलीवर किया और गुजरात को बहुत आगे बढ़ाया, तो देश के अंदर, लोगों के अंदर भी एक आशा उत्पन्न हुई कि राष्ट्र को भी आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्र ने उनको अवसर दिया। देश की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है। पार्टी भी ठीक ढंग से, समय से पहचान करके निर्णय लेने में कामयाब रही और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को सशक्त किया है है, सशक्त करने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार की दीर्घकालीन योजना के साथ एक निर्णय किया है कि हमें इस विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। हर प्रकार से आत्मिक पैमाने पर जो उन्होंने चिंता की है वह सच में बहुत सराहनीय है। ऐसे राष्ट्र पुरुष को मैं नमन करता हूं और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको लंबी आयु दे और उनकी सोच, उनका सपना जल्दी पूरा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्रीमती शिखा राय जी।

श्रीमती शिखा रॉयः धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे प्रथम तो चैत्र नवरात्रों की सबको बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में ये एक ऐसा काल है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गुड गवर्नेंस क्या होती है। सरकार के माध्यम से आप सच में अपने देश की भलाई के लिए देश को डेवलपमेंट के मोड़ पर कैसे डाल सकते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने इस पूरे कार्यकाल में करके दिखाया है। आज देश का युवा उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है कि जैसा मोदी जी करते हैं मुझे वैसा करना है। इस सरकार की विश्वसनीयता जो उन्होंने जनता में बनाई है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से देश को विकास की राह पर ले जा सकता है। ये उनके कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। आज इंटरनेशनल रिलेशंस में देख लें, तो दुनिया में जहां एक दूसरे के प्रति दुरभावना से युद्ध हो रहा है, वहां हमारे देश की प्रगति कहीं रुक नहीं रही है। ये उनकी उस सोच का नतीजा है जो उन्होंने दुनिया भर में अपने देश की जो साख बनाई है, जो उसकी विश्वसनीयता बढ़ाई है, ये उसी के कारण है कि आज हमारा देश इन परिस्थितियों में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। गुड गवर्नेंस शब्द हम केवल सुनते थे। सुशासन क्या होता है। लेकिन सही मायने में उस व्यक्ति तक जिस तक सरकार नहीं पहुंचती थी या जो सरकार तक नहीं पहुंच पाता

था उस व्यक्ति तक भी सुशासन पहुंचा। इसी तरह से संपूर्ण रूप से सबको साथ लेकर के चलने की जो विधि से उन्होंने इस देश को चलाया है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जांपल है। वो जो राजनीति में आना चाहते हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं उनके लिए उनका ये कार्यकाल एक रोल मॉडल की तरह चलेगा। दिल्ली की सरकार का एक वर्ष पूरा हुआ है। मैं उसके लिए भी अपनी मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं कि इस एक साल के सुशासन का जो उन्होंने मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए दिखाया है। उसमें जनता का विश्वास सरकार में और सरकार की कार्यप्रणाली में बढ़ा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: शॉर्ट में रखना है आधा-आधा मिनट। श्री तरविंदर सिंह जी।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: आज मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने 8931 दिन पूरे, 1930 का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रधानमंत्री जी मैं आज की बात करूं जो 25 दिन से जो ईरान में जो हमला हो रहा है अमेरिका इनका युद्ध चल रहा है हिंदुस्तान में 144 करोड़ लोगों को जो आज लगातार 24 दिन से, 24 दिन से लगातार और पेट्रोल गैस लेकिन प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से आज हमारे देश में ये किल्लत नहीं आ रही और हमारा देश शांति से चल रहा है। आप चारों तरफ देखो पूरे वर्ल्ड में आज क्या-क्या हालात बने हुए हैं। कहां पर क्या झगड़ा हो रहा है। कहां पर और लेकिन हमारे देश में तो इतने धर्म है। अगर 100 किलोमीटर पार करो तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हुआ। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी आज समझ रहे हैं। उस दिन मैंने देखा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी ओथ ले रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज से मैं आपका कार्यकर्ता हूं, इतने नरम दिल के प्रधानमंत्री। आज हिंदुस्तान को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया। आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बहुत- बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविन्दर सिंह लवली जी।

श्री अरविन्दर सिंह लवली: अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है कि देश का नेतृत्व एक ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जिनका नेतृत्व मैं समझता हूं कि इतना लंबा समय रहा हो कि वह अपने आप में एक हिस्टोरिक मूवमेंट और रिकॉर्ड क्रिएट करता हो। आज 8932 दिन हो गए हैं उनको गुजरात के मुख्यमंत्री से ले के और देश के प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए और इतना लंबा सफर जो है वो relentless service

का है इस देश के प्रति। उनकी जर्नी जो है वो कमिटमेंट, करेज और, मैं समझता हूं कि नव भारत के निर्माण की कहानी अगर जो है उनकी जर्नी लिखती है। अध्यक्ष जी, निश्चिततौर पर देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है। मेरी व्यक्तिगत रूप से, पिछले पांच- छह प्रधानमंत्रियों को मैंने नजदीकी से काम करते हुए देखा है, वो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते थे, उनसे इंटरेक्शन मेरी पिछली पांच- छह प्रधानमंत्रियों से थी। लेकिन इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है कि जो नेतृत्व शक्ति, जिस तरीके के निर्णय लेने की शक्ति, जिस तरीके से गवर्नेंस के मॉडल को आगे बढ़ाने की जो है कार्यक्षमता जो नरेंद्र मोदी जी में है उसका कोई दूसरा एग्जाम्पल देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिला, ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया है और ना केवल देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर जो है उन्होंने राष्ट्र के सम्मान को, भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। तो इस मौके पर जहां हम उनको बधाई करते, बधाई देते हैं वहां उनको जो है हम सैल्यूट भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में इसी तरीके से भारत, हिंदुस्तान रोज नई ऊंचाइयां छुएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय सदस्य- राजकुमार भाटिया जी और उसके बाद मुख्यमंत्री जी।..... आप भी।

श्री राज कुमार भाटियाः आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय द्वारा इस विशेष विषय पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे ये अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लोक सेवक के रूप में 8932 दिन पूर्ण होने पर आज दिल्ली की इस प्रतिष्ठित विधानसभा में जो चर्चा हो रही है एक लोक सेवक के रूप में, एक संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में और नए भारत के निर्माण में, चाहे वह 'सबका साथ सबका विकास' हो, 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' हो या भारत की गौरवशाली परंपरा को विश्व पटल पर रखने की जो गरिमामय पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है उससे हर भारतीय का सम्मान बढ़ा है, हर भारतीय का मस्तक भी ऊंचा हुआ है। आज हम गर्व के साथ विश्व पटल पर भी भारत की गौरवशाली परंपरा को रखने में सफल हुए हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुकरण करते हुए दिल्ली के बजट को, दिल्ली के विकास को सर्वस्पर्शी बनाने का काम किया है उसी के नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज इस विधानसभा में एक विशेष अभिनंदन प्रस्ताव पारित

करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री- श्री प्रवेश साहिब सिंह जी।

श्री प्रवेश साहिब सिंह (माननीय मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो रिकॉर्ड अपने आप ही बनते चले जाते हैं। हमने देखा कि गुजरात में अर्थक्वेक के बाद में जब वहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और वहां पर पूरी स्थिति को संभाला था। ऐसे ही जब देश में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और अखबार खोलते ही हर रोज हमको एक नया स्कैम दिखाई देता था, वैसी स्थितियों में 2014 में प्रधानमंत्री- नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली थी। और यह मुझे कहते हुए हर्ष होता है और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर हमको, हम सबको गर्व होता है कि पिछले 11 सालों में एक भी पैसे का घोटाला, कोई भारत सरकार के ऊपर में एक भी पैसे का घोटाला नहीं लगा पाया, एक भी पैसे का आरोप नहीं लगा पाया, यह सबसे बड़ी बात है। आज मैं, हम सारे सदस्य ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को लंबी आयु दें, स्वस्थ जीवन दें और जब तक उनका स्वस्थ शरीर रहे तब तक वह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहें ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जिनको हर वर्ग का आशीर्वाद है, हर वर्ग का प्यार है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे पूरे विश्व में बैठा कोई भी एनआरआई हो, आज देश का कोने-कोने का बच्चा, बजुर्ग, महिला सब उनको अपना आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, वह इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने विकास को केवल कोई शहरों तक सीमित नहीं रखा, वह अपने विकास को एक-एक गांव तक, एक-एक ट्राइबल एरिया तक, देश के कोने-कोने तक लेकर गए और यही कारण हैं कि ना जाने कितने देशों ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, यह भी बहुत हमारे लिए गर्व की बात है।

जब मैं सांसद था आदरणीय अध्यक्ष जी तब मेरा उनसे मिलना हुआ। और मैंने उनके सामने जब जाकर अपनी दो मांगे रखी कि एक वहां पर नजफगढ़ में हॉस्पिटल है जो पिछले 25 साल में नहीं बना और एक जो है हमारी दिल्ली की मुख्य सड़क थी यूईआर टू और मैं आपको बताना चाहता हूं पहली मीटिंग में 1 मिनट के अंदर-अंदर उन्होंने दोनों

प्रस्तावों को मंजूरी दी और 100 करोड़ रूपये हॉस्पिटल के लिए दिया और 8000 करोड़ रूपये यूईआर टू के लिए दिया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं।

मैं आज आपको यहां पे एक अपना संस्मरण भी जो मैं उनके किस बातों से प्रभावित होता हूं कि जब उनकी माताजी का निधन हुआ और हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसे राजनायक की जो हेड ऑफ द स्टेट हों अगर उनके परिवार में कोई मृत्यु होती है तो पूरे देश के, ना जाने गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, ना जाने कितने हजारों लोग अपने सारे सरकारी साधनों का उपयोग कर कर वहां पर जाते हैं, समय देते हैं, मगर जब उनकी माता जी का निधन हुआ तो वह प्रधानमंत्री के रूप में नहीं एक बेटे के रूप में उन्होंने पूरे देश के गवर्नर को मना कर दिया, मुख्यमंत्रियों को मना कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर को मना कर दिया, देश के हर वीवीआईपी आदमी को मना कर दिया कि यहां पर आके, आप अपने-अपने क्षेत्र में काम कीजिए, अपने राज्य का काम कीजिए, जनता का सेवा कीजिए। यहां पर मैं अपनी माताजी को जो उनका अंतिम संस्कार है उसको बेटे के नाते मैं पूरा करूंगा, आप यहां पर आके समय मत खराब करिए, आप आके, देश में अपने कामों में लगे रहिए। इस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। ना उनको नींद आती है, ना उनको चैन आता है, ना उनको आराम आता है।

मैंने आज तक प्रधानमंत्री जी के साथ में जब मैं सांसद था या जब हम उनको रैलियों में देखते हैं, हम उनको मंच पर देखते हैं, एक-एक दिन में चार-चार राज्यों में दौरा करते हैं। आज तक मैंने उनको कभी भी उबासी लेते हुए नहीं देखा। एक बार भी किसी ने भी किसी मीडिया चैनल में कभी प्रधानमंत्री जी ने उबासी हमने उनको लेते हुए नहीं देखा। यह दिखता है कि वह पूरे दिन में 24 घंटे में शायद वह 24 घंटे ही काम करते हैं, ऐसे हमें प्रधानमंत्री जी मिले यह हमारा सौभाग्य है। 8931 दिन जो उन्होंने पूरे किए हैं, मैं चाहता हूं कि जब तक हम लोग हैं तब तक वह ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री बने रहें, ऐसे ही प्रधान सेवक के रूप में काम करते रहें। हम सबकी तरफ से उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री- श्रीमती रेखा गुप्ता जी।

श्रीमती रेखा गुप्ता (माननीया मुख्यमंत्री): अध्यक्ष जी, नेता नहीं नायक, शासक नहीं सेवक और सिर्फ कार्य नहीं विजन के साथ में काम करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री- आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब की ओर से, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं बधाई

देना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं। जिन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं बदल दी। ईमानदारी किसे कहते हैं वो देश और दुनिया को बताया। मेहनत किस तरह की जा सकती है यह जनमानस के समझ में आया। देश के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति कर्तव्य ये उनके हर आचरण में हम सबने देखा, प्रत्येक दिन देखा। एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर 24X7 365 दिन किस तरीके से देश हित में काम किया जाता है, यह लगातार पूरी दुनियां, पूरा देश, हर व्यक्ति देख रहा है। देश का मान-सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला व्यक्तित्व है। जिन्होंने अपनी जन-नीतियों के द्वारा विदेश नीति के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा देश को गड्ढों से निकाल कर के एक नई इमारत बना करके दी जिसमें देश के हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित है। मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, समस्त जनता को कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने शासन के माध्यम से transparency,accountability और टीम वर्क जिन्होंने तकनीक से लेकर के अपनी भविष्य की एप्रोच तक हर दिशा में भारत देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज अपने दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में चाहती हूं कि हम सब मिलकर के इस अभिनंदन प्रस्ताव को पारित करें और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत शुभेच्छाएं शुभकामनाएं प्रेषित करें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज का यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर 8931 दिन सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा पूर्ण कर पूर्व सिक्किम मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 8930 दिनों का रिकॉर्ड पार कर लिया है। यह 25 वर्षों का अखंड जनसेवा का प्रमाण है। 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ से लेकर 26 मई, 2014 को देश के प्रधानमंत्री बनने तक मोदी जी की यात्रा एक निष्ठ समर्पण की यात्रा रही है। वे पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में पूर्ण बहुमत से लगातार दो कार्यकाल पूरे किए और तीसरी बार भी सत्ता में लौटे। उनके नेतृत्व में भारत में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले और देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री आशीष सूद जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया वो सदन के समक्ष रख रहा हूं।

जो उसके पक्ष में है वो हां कहें

जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। सर्वप्रथम श्री कुलवंत राणा माननीय सदस्य।

विशेष उल्लेख(नियम-280)

श्री कुलवंत राणा: धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ये माइक ऊपर कराना पड़ेगा छोटा है नीचे रहता है। माइक बहुत नीचे रहता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आवाज पूरी आ रही है आपकी।

श्री कुलवंत राणा: ठीक है अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय विशेष उल्लेख के द्वारा जो मुझे आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार। मैं एक चिंता प्रकट कर रहा हूं दिल्ली की और मुख्य रूप से देश की भी है यह कि पूरे दिल्ली में एक खाद्य पदार्थों में जो मिलावट का मामला है। एक बुजुर्ग आदमी जब बीमार हो जाता है तो घीया खाता है, तोरी खाता है उसमें भी इंजेक्शन लग जाता है। भिंडी में रंग लगाया जाता है, मिर्च पर रंग लगाया जाता है, करेले पर रंग लगाया जाता है और पेस्टिसाइड बहुत भारी मात्रा में उपयोग होते हैं, फर्टिलाइज़र्स बहुत भारी मात्रा में उपयोग होते हैं और एक डर रहता है, भय का वातावरण रहता है देश के और दिल्ली के नागरिक में कि क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। आम आएगा अभी तो आम में भी बहुत सारे मसाले लगाए जाएंगे। ऐसे ही जानकारी मिलती है कि आम खाने के बाद ऐसा मसाले वाला कैंसर भी होता है। नकली दूध आमतौर पे टीवी में और समाचार पत्रों में छपता रहता है ये यहां पकड़े गए, ये पकड़े गए, वहां पकड़े गए नकली देसी घी। ऐसी फैक्ट्रियां हमारे आउटर दिल्ली में कई पकड़ी गई हैं। नकली पनीर शायद आप मुझे लगता नहीं की सार्वजनिक किसी विभाग में क्षेत्र में आप रसगुल्ला या गुलाब जामुनों का सेवन करते होंगे, पनीर की सब्जी खा पाते होंगे। डरते हैं आप भी शायद नहीं खाना खाना। तो ये बहुत भयावह स्थिति है और एक मजाक है मानवता के प्रति। चाहे वो दूध में हो, घी में हो, पनीर में हो, सब्जियों में, फलों में हो और दवाइयों को भी नहीं छोड़ा गया नकली दवाएं भी। ये कहने में तो बहुत छोटा सा लगता है अध्यक्ष जी मानवता के दृष्टिकोण में है। मानवता के साथ खिलवाड़ है ये और ये घातक है और ये सब चलता रहेगा रुक नहीं पाएगा। इसमें अच्छी सजाओं का प्रावधान नहीं है। अगर इसके अंदर कठोर सजा

का प्रावधान हो, नॉन बेलेबल हो और फांसी की सजा का प्रावधान अगर इसमें हो तो इस पर रोक लग सकती है नहीं तो इंस्पेक्टर प्रणाली वो भी सेट होती है। अगर घी बनता है कहीं भी पहले सबसे पहले वहां का बीट अफसर को मालूम होता है। अगर एक कंस्ट्रक्शन भी शुरू होती है ना ईंट आती है किसी के यहां भी अध्यक्ष महोदय तो फटाफट सिपाही पहुंच जाता है वहां। पोलूशन की बात थी पीछे पोलूशन पर अभी कहां पर ओपन में आग जल रही है वो एक मिनट में रुकवा सकता है, अपराध को एक मिनट में रोक सकता है सिपाही और नकली आइटम पूरे देश में नहीं मिल सकती अगर सिपाही की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो। सिपाही हर जगह शामिल होता है। जो फूड इंस्पेक्टर है वो कितने सक्रिय हैं, उतने सक्रिय नहीं हैं। लैब्स की भी कमी है, टेस्ट लैब भी कम हैं, उसमें इक्विपमेंट्स भी कम है। मुख्य रूप से यह एक बहुत गंभीर विषय है और हमको संवेदनशीलता के साथ पूर्ववर्ती सरकारों से चलता आ रहा है यह मामला, लंबे अरसे से आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर भी काम करेगी और ऐसा करके हम कितने लोगों का जीवन बचा पाएंगे। ऐसे अध्यक्ष महोदय मैं आपकी जानकारी में लेकर आ रहा हूं। पिछले 10 साल में दो से तीन लाख केस सामने आए हैं, दो से 3 लाख। पाम ऑयल है, पाम ऑयल से भी कैंसर होता है सुनने में आया है। वो भी घातक है उसका भी विकल्प निकालना पड़ेगा या उसके अंदर वो जो पदार्थ है जिससे कैंसर होता है तो उसको भी रिसर्च की आवश्यकता है कि उसके अंदर वो कौन सा मटीरियल है जो घातक है उसको अलग किया जा सकता है क्या। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी रिसर्च की भी आवश्यकता है, बहुत सारे कदम उठाने की भी आवश्यकता है और दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को एक हेल्दी फ़ूड दे पाएं और आदमी बेझिझक उसका सेवन कर पाए ऐसा वातावरण बनाने की भी आवश्यकता । तो आपने मुझे समय दिया, विषय बहुत लंबा है अब आंकड़े भी मैं इसमें बहुत सारे मेरे पास हैं मैं दे सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस पर सदन का समय ज्यादा लंबा लूं। तो मैं सरकार से भी चाहूंगा इसमें बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस विषय को देखते हुए गंभीरता को देखते हुए हम इस पर कठोर कानून बनाने और कठोर कानून बना करके इस प्रकार की मिलावटों पर रोक लगाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य डॉ. अनिल गोयल जी।

डॉक्टर अनिल गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझको रूल 280 के तहत आपने बोलने का मौका दिया। मैं सरकार का ध्यान उन लोकतंत्र सेनानियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने 1975-77 के आपातकाल के दौरान कारावास, उत्पीड़न व कठिनाइयों का सामना करते हुए लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में ऐतिहासिक योगदान दिया और हम सब जानते हैं कि भारत का

लोकतंत्र केवल सुविधाजनिक संवैधानिक प्रावधानों से ही नहीं बल्कि नागरिकों के त्याग और संघर्ष से सुदृढ़ हुआ है। खेद है पिछली सरकारों ने इनके सम्मान पर कोई ध्यान नहीं दिया जबकि भाजपा शासित जितने राज्य हैं उनमें इनकी सम्मान राशि और सम्मान का भी ध्यान रखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सेनानियों की पीड़ा को समझा और उन्हें सम्मानित करने की ऐतिहासिक घोषणा दिनांक 28 मई, 2025 को की और मेरा यह भी कहना है कि अधिकांश सेनानी वरिष्ठ नागरिक हैं और विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और एक साथ में निवेदन भी करना चाहता हूं कि दिल्ली के लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन हेतु प्रक्रिया शुरू की जाए। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, निशुल्क चिकित्सा अन्य सुविधाएं और सार्वजनिक सम्मान करने के लिए नीति जो तैयार हुई है उसको लागू किया जाए क्योंकि मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन लोकतंत्र रक्षकों के त्याग को सम्मान देते हुए समयबद्ध सीमा के भीतर इस योजना को क्रियान्वित करने की कृपा करें क्योंकि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान केवल एक प्रशासनिक निर्णय ही नहीं बल्कि राष्ट्र की लोकतांत्रिक चेतना के प्रति प्रतिज्ञा का प्रतीक है। मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी आपकी पहल से इस दिशा में जल्दी ही सकारात्मक प्रगति होगी धन्यवाद, जय हिंद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुरेंद्र कुमार(अनुपस्थित), माननीय सदस्य श्री प्रवेश रत्न(अनुपस्थित), माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय जल मंत्री, हमारी सरकार को लगभग एक साल हो गया है नालों की बात करें या पीने के पानी की बात करें अनेकों अनेक योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई और उनको क्रियान्वित करने का प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल मंत्री जी ने यमुना की सफाई और यमुना में जो नाले डलते हैं उनको रोक कर उनकी सफाई के साथ बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए लेकिन पिछले 20 साल से दिल्ली में सीवर और वाटर की जो लाइन है वो बहुत पुरानी होने की वजह से दोनों में ही कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है। समय सरकार को बहुत कम मिला है लेकिन उसके बावजूद हमारे यहां कुछ कॉलोनियों में पुरानी लाइनें होने की वजह से पानी और सीवर की बहुत समस्या आ रही हैं। आप, जल मंत्री जी मैं यह समझता हूं कि आप पूरी दिल्ली की समस्या का तो निदान करेंगे लेकिन अभी जो त्वरित रूप से यहां पर जो समस्या आ रही हैं उनको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था आनंद विहार के सभी ब्लॉक, मानक विहार,

जागृति एन्क्लेव, योजना विहार में पीने के पानी में सीवर का गंदा पानी मिलकर आ रहा है। सभी सीवर उफान पर हैं इसकी वजह से क्षेत्र में पेयजल का घोर संकट बना हुआ है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पुराने जर्जर हो गए पीने के पानी की और सीवर की लाइन को प्रायोरिटी पर बदला जाए जिससे कि मेरी क्षेत्र की जनता को पीने का स्वच पानी उपलब्ध हो सके, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अनिल झा(अनुपस्थित), माननीय सदस्य श्री अजय कुमार महावर जी।

श्री अजय कुमार महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने 280 पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिल्ली की जो सबसे पहली मेट्रो लाइन बनी थी जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उस समय बस अड्डे से और सीलमपुर वाली शाहदरे वाली जो लाइन है उसमें एक स्टेशन है शास्त्री पार्क स्टेशन। शास्त्री पार्क स्टेशन में जब हम बस अड्डे से शाहदरे की तरफ जाते हैं तो दाहिनी ओर का एग्जिट है, बाई ओर एग्जिट नहीं है तो दाहिनी ओर की एग्जिट होने के कारण गांधी नगर और लक्ष्मी नगर तक के लोगों को जाने का एक्सेस मिल जाता है लेकिन बाई और एग्जिट ना होने के कारण जो पूरा हमारा इलाका है उस्मानपुर, पहला पुस्ता, गढ़ी मेंडू, जगजीत नगर, करतार नगर ये सारा इलाका जो है उनको बहुत दूर शाहदरा जाना पड़ता है, सीलमपुर जाना पड़ता है फिर वहां से वापस आना पड़ता है तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को कि वह बहुत पुरानी लाइन है अच्छी लाइन है उसका खाली बाएं साइड का एग्जिट खोल दें जो बाबा श्यामगिरी की तरफ खुलता है यानि कि जीटी रोड की तरफ खुलता है। जीटी रोड की तरफ एग्जिट खुलते ही इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा और हमारे क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयल: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान एक दिल्ली के निजी अस्पतालों की बढ़ती मनमानी के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि जब कोई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती होता है उसके पास डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपको अस्पताल में भर्ती होना है। उसके पास रिपोर्ट होती है उसी के आधार पर भर्ती किया जाता है लेकिन भर्ती होने के तुरंत बाद ही वह दोबारा सारे टेस्ट किए जाते हैं और वह टेस्ट यदि उनकी उसी

लैब से टेस्ट कराए जाए तो 3000-4000 के 89 टेस्ट का पैकेज होता है लेकिन उसी टेस्ट को कई गुना रेटों पर किया जाता है। जिससे कि अस्पताल का बिल कई गुना बढ़ जाता है और देखने में यह भी आया है कि ग्लव्स हैं, मास्क हैं। उन सभी छोटे-छोटे सामान के पैसे निजी अस्पताल पेशेंट से लेते हैं और कमरों की कोई दर सीमा तय नहीं की जाती और ना कहीं लिखा जाता है जिससे कि व्यक्ति को देखकर वो रेट से उसको चार्ज किए जाते हैं जबकि डीजीएचएस और सीजीएचएस के तहत यही अस्पताल कम दरों में इलाज करते हैं उसके बावजूद वहां पर कोई रेट लिस्ट नहीं होती, पारदर्शिता का अभाव भी है और साथ में कई मामलों में डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं हॉस्पिटल में लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स की फीस चार्ज की जाती है जबकि बताया जाता है कि वो टेलीफोनिक आपकी कंसल्टेशन दे रहे हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और यह भी देखने में आया है कि ईडब्ल्यूएस के जो हमारे श्रेणी के मरीज हैं उनको अस्पतालों में हमने भी कई बार फोन करते हैं तो बेड फुल बताकर कहा जाता है कि बेड फुल हैं आपके कोई इसकी पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्देश में वर्ष 2018 के निर्णय के अनुसार रियायती भूमि पर बने निजी अस्पतालों के लिए 10% आईपीडी इनडोर पेशेंट डिपार्टमेंट और निशुल्क देना अनिवार्य है और 25% ओपीडी सेवाएं निशुल्क देना अनिवार्य है। दिनांक 24 फरवरी, 2026 को 51 निजी अस्पतालों को अवमानना कंटेंप्ट नोटिस जारी किए गए हैं और जिसमें विशेष सब बड़े अस्पताल नाम लेना जैसे सर गंगा राम, मूलचंद, मैक्स, फोर्टिज जैसे अस्पतालों में नियमों का कम पालन पाया गया केवल एक से 10% इसको क्या नाम है आईपीडी और ओपीडी की सेवाएं दी गईं। दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया जो अनुपालन की निगरानी करेंगे DDA, L & DO and MCD को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने के निर्देश दिए गए और मेरी आपसे निवेदन है आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन हैं कि रेट लिस्ट सीजीएचएस, डीजीएचएस रेट हैं क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग जाते हैं उनका कोई भी जो उनको आपके डिस्काउंट मिलना चाहिए या उनको रेट मिलने चाहिए एक पारदर्शी वैल्यू के साथ में कि वहां पर होना चाहिए अनिवार्य किया जाए और साथ में क्योंकि जो दवाइयां भी होती हैं ये जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनको 25% तक डिस्काउंट पे लेते हैं लेकिन उसके फुल वैल्यू चार्ज की जाती है और वही दवाई बाहर आपके 10 से 15% कम में मिलती है और कई बार तो दवाइयां अन्नेसेसरी मंगा ली जाती है उनके भी रेट चार्ज किए जाते हैं और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कोटे के जो मरीज हैं हमारे उनके जो नोडल ऑफिसर

अपॉइंट किए गए हैं वो स्थानीय विधायक जो है जहां हॉस्पिटल है उनको बताएं उनकी पारदर्शिता भी बढ़ाई जाए जिससे कि आने वाले समय में विधायक भी अपने जो क्योंकि जनता हम सभी के पास आती है जिससे कि हम उनकी सेवा कर सकें और ये हॉस्पिटल नो प्रॉफिट नो लॉस वाली व्यवस्था में होने चाहिए ना कि प्रॉफिट मेकिंग व्यवस्था में होने चाहिए। बस मैं यही आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि कई बार मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत चलते हुए वही ढर्रा जो दूसरे पेशेंट हैं जो मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लेते हैं उनसे भी उतने ही रेट चार्ज किए जाते हैं। इस पर एक अच्छे से ये विषय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से जुड़ा हुआ है इसलिए शीघ्र ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है और आम जनता को न्याय मिल सके और स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका विशेष धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संदीप सहरावत जी।

श्री संदीप सहरावत: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी विधानसभा क्षेत्र सहित दिल्ली की विभिन्न क्षेत्रों में वर्षों से लंबित मास्टर प्लान और लैंड पुलिंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है और जब तक मास्टर प्लान तथा भूमि पुलिंग योजना प्रभावी रूप से लागू नहीं होती तब तक कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण निरंतर जारी है। अध्यक्ष जी हमारी विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर खेती योग्य भूमि को अवैध रूप से काटकर छोटे-छोटे प्लॉट बनाए जा रहे हैं। इन कॉलोनियों का ना तो कोई स्वीकृत नक्शा है और ना ही कोई नियोजित ढांचा। परिणाम स्वरूप भविष्य में वहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सीवर, सड़क तथा पार्क से वंचित रहना पड़ता है। पूर्व में कटी हुई कॉलोनियों की स्थिति यह है कि यहां पर ट्रांसफार्मर लगाने तक की जगह नहीं है और वह लोग परेशान होकर हमारे पास आते हैं क्योंकि उनका यूडी में नक्शा नहीं है, पीएम उदय में उनका नक्शा नहीं है ना वहां पर सड़क बन पा रही है, ना पानी की लाइन डाल पा रहे हैं। इसी तरह वर्तमान में भी बन रही कॉलोनियां भी उसी ढंग से विकसित हो रही है जहां ना तो उचित जल निकासी है ना ही पर्याप्त सड़क चौड़ाई क्योंकि और ना ही कोई सार्वजनिक स्थान यहां पर बनाए जा रहे हैं। गरीब एवं निम्न वर्ग के लोग मजबूरी में छोटे-छोटे प्लॉट तो ले लेते हैं परंतु भविष्य में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती जिससे उनके जीवन स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है तथा दिल्ली के नियोजित विकास को भी नुकसान पहुंचता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृषि भूमि पर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को रोका जाए। मास्टर प्लान

और लैंड पुलिंग को शीघ्र लागू किया जाए। जिस तरह हरियाणा में दीन दीनदयाल आवास योजना है, उसी के तर्ज पर दिल्ली में भी एक सुव्यवस्थित योजना लागू की जाए ताकि आम नागरिक को वैध योजनाबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध हो सके, धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय उपसभापति श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के तहत एक विशेष उल्लेख के तहत बोलने की इजाजत दी उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद एसी 69 के अंतर्गत घनी आबादी और बढ़ते हुए घनत्व क्षेत्रफल के अनुसार बच्चों के पढ़ने के लिए पर्याप्त स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा शिक्षा विभाग को बार-बार पत्र भी लिखा गया। यही नहीं जब मैं 1998 और 99 में दिल्ली विधानसभा का सदस्य बना था। उस समय मैंने एक जमीन को चिन्हित किया और अध्यक्ष महोदय चिन्हित ही नहीं उस जमीन पर स्कूल खोलने के लिए मेरे द्वारा वहां पर उसकी चारदीवारी वगैरह करने का काम भी किया गया था। पिछले दिनों के अंतर्गत जब राजस्व विभाग द्वारा अनओथराइज कॉलोनीज में काम ना करना और अनओथराइज कॉलोनीज का डेवलपमेंट ना होना एक बहुत बड़ी समस्या बनी। तो उस समय में इन अनओथराइज कॉलोनीज हो या ग्रामीण क्षेत्र हो इन गांव की जमीनों को डीडीए को पक्की रजिस्ट्री या मालिकाना हक या डेवलपमेंट के लिए उसको दिया गया बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, डीडीए के नकारात्मक रवैये के कारण दिल्ली की यह बुरी दशा तो हुई लेकिन यह भी सत्य है डीडीए की नकारात्मक लेट लतीफी के कारण मुस्तफाबाद जैसे क्षेत्र के अंतर्गत आज स्कूल नहीं खोल पा रहा है। स्कूल ही नहीं खुल पा रहा है इस जमीन को सिर्फ हैंड ओवर और टेक ओवर करना है। वो भी हैंड ओवर और टेकओवर करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को उस जमीन को देना है। 1600 वर्ग मीटर जमीन उसको एक छोटा सा काम है। लेकिन उस काम को हैंड ओवर और टेक ओवर नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से आज वहां स्कूल नहीं खुल रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह भी उस जमीन का यह भी सत्य है कि 37/18,18/1 की यह जमीन में आज तक स्कूल ना खोलने के कारण प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है। वो लोग मनमाने फीस ले रहे हैं और गरीब का बच्चा आधी में ही पढ़ाई को छोड़ देता है। स्कूल नहीं जाता है और बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को इस डीडीए संबंधी इन जिन अधिकारियों के लेट लतीफे के कारण वहां स्कूल नहीं खोल पा रहे। लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसको तुरंत एजुकेशन

डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए जिससे यहां स्कूल खुले। इसके लिए मेरी क्षेत्र की जनता आपकी सदा आभारी रहेगी, मेरी सरकार की आभारी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री चंदन कुमार चौधरी।

श्री चंदन कुमार चौधरी: मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, अभी तक किसी अध्यक्ष का और किसी विधायक का और किसी भी मुख्यमंत्री का ध्यान संगम विहार की ओर नहीं गया था। लेकिन हमारी सरकार आते ही सभी बुनियादी सुविधाएं मिल रही है और उस पर तेजी से काम हो रहा है। लेकिन एक विशेष बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक भी आरोग्य मंदिर नहीं खुला है। एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। एक भी अस्पताल नहीं है। उसका एकमात्र कारण है कि हमारे पास जमीन नहीं है। डीडीए के पास जमीन है और उस डीडीए की जमीन पर माफियाओं के द्वारा शेड डालकर के बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां चलाई जा रही है। अवैध पार्किंग चलाए जा रहे हैं। यदि हमारे किसी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा नाली बनाने का काम यदि मटेरियल बनाने का काम डीडीए की एक इंच जमीन पर यदि कर दिया जाता है तो उनको नोटिस दे दिया जाता है। उसके बाद जब हम नोटिस लेटर पर लेटर लिखते हैं डीडीए को तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल एक झांसा दिया जाता है कि अगले हफ्ते हो जाएगा। इस महीने हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा। लेकिन मैं डीडीए की ओर से नकारात्मक बातें भी नहीं करूंगा क्योंकि सीएम साहिबा की विशेष कृपा से प्रवेश जी की कृपा से और हमारे सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी की कृपा से और मेरी मेहनत की वजह से सारे मतलब ढाई एकड़ जमीन हमें जल बोर्ड को मिला है जो यूजीआर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और प्रवेश जी से आग्रह भी करता हूं जल्द से जल्द उस यूजीआर का निर्माण हो जो कि जल की समस्या जो मेरे क्षेत्र में है वो समाधान हो सके। लेकिन विशेष बात यह है अध्यक्ष जी, कि यदि डीडीए की जमीन माफियाओं के द्वारा कब्जा हो रहा है। उस पर कब्जा नहीं खाली किया जा रहा है। अवैध रूप से पैसे कलेक्शन करके डीडीए को जा रहा है। बहुत सारे लोगों को जा रहा है और हमारे यहां एक भी स्कूल नहीं है 12th का। एक भी आरोग्य मंदिर नहीं है, एक भी अस्पताल नहीं है। तो विशेष ध्यान आकर्षित करता हूं आपका कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और हमारे क्षेत्र में आरोग्य मंदिर, स्कूल और अस्पताल खोले जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधानसभा के पटल पर दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 प्रस्तुत करती हूं। [1]

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये आर्थिक सर्वे सभी सदस्यों को नेवा के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाए। वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

वित्तीय समितियों का निर्वाचन

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 192 के उपनियम दो नियम 194 के उपनियम दो और नियम 196 के उपनियम दो के अनुसार अनुसार इस सदन के सदस्य 1 अप्रैल 2026 से आरंभ होने वाली कार्य अवधि के लिए लेख लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से नौ नौ सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद अब ये प्रस्ताव सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: आदरणीय अध्यक्ष जी।

[1] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23549 पर उपलब्ध।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: एक सेकंड कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

समितियों के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।[2]

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण-2 श्री अजय महावर लोकलेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री अजय महावर: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। पहली पीएसी की रिपोर्ट स्वास्थ्य पर है। आपके माध्यम से कुछ तथ्य के साथ मैं इसको सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष में सीएजी की सार्वजनिक स्वास्थ्य और संरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिबंधन पर रिपोर्ट वर्ष 2024 की रिपोर्ट संख्या तीन से संबंधित है। यह रिपोर्ट 28 फरवरी, 2025 को सदन के समक्ष रखी गई थी। समिति ने अपने बैठकों में रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की। विभाग द्वारा प्रस्तुत ATNs और समिति के समक्ष मौखिक बयान के आधार पर इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। यहां मैं माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने सीएजी की रिपोर्टों को सदन में छुपाया था। अध्यक्ष जी तब आपको ही इसे विधानसभा में रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा था। रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अपने पहले ही सत्र में जनता को किए गए अपने वादे के अनुसार सीएजी की रिपोर्ट सदन के समक्ष में प्रस्तुत की। यदि ये रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती तो सरकार पहले ही सुधारात्मक कारवाई कर सकती थी। दिल्ली के लोगों के खराब स्वास्थ्य सेवाओं का सामना नहीं करना पड़ता दिल्ली के लोगों को। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर भी हैरानी होगी कि पीएसी कमेटी की ये रिपोर्ट 16 साल बाद इस सदन में रखी जा रही है। 16 साल तक कोई रिपोर्ट इस सदन में नहीं आई। आखिरी रिपोर्ट 2009 में पेश की गई थी 9, 10 में। लोकपाल के नाम पर दिल्ली को गुमराह करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब सत्ता में थी तो समिति को निष्क्रिय कर दिया था। शायद ही कोई बैठक हुई हो। हमारी माननीय Leader of Opposition आतिशी जी इसकी सभापति रही हैं दो वर्ष। लेकिन वो भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर सकीं। उसमें विफल रहीं। पीएससी को संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक माना जाता है। ये विधायिका की ओर से एक प्रहरी की भूमिका निभाती है ताकि कार्यपालिका द्वारा विधानसभा द्वारा स्वीकृत

[2]दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23564 पर उपलब्ध।

धन पर जवाबदेही की जांच की जा सके। उन्होंने पीएसी को पंगू बनाया और इसके बाद एक भी सीएजी की रिपोर्ट सदन के सामने पेश नहीं की अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट में 2016 से 22 तक की अवधि को शामिल किया गया। इसमें केजरीवाल मॉडल के बारे में आम आदमी सरकार के खोखले दावे की विफलता को पूरी तरह से उजागर किया है। इस परफॉर्मेंस ऑडिट में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं की व्यापक रूप से जांच और विश्लेषण किया गया है। हेल्थ सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, availability of drugs, medicines, equipment of other consumables, health infrastructure, financial management, outcome of centrally sponsored schemes, regulatory mechanism, sustainable development goals 3 यहां तक कि progarms, schemes, projects, services of GNCTD आयुष ये सभी तात्कालिक सरकार ने किसी भी मानदंड में निर्धारित मानक को पूरा नहीं किया। ये कमेटी की रिपोर्ट में हमने पाया है। इसे पूरा करने में असमर्थ रही। इसके विपरीत दावे किए गए। 10 वर्षों से लंबित कार्य को पूरा करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया। कई वर्षों तक अस्पतालों, औषधालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां रहीं। इसके लिए भी पिछली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। विभाग ने कोई कदम नहीं उठाए। कर्मचारियों की कमी के कारण स्वास्थ्य संस्थानों पर कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा। यहां तक कि दिव्यांग जन जो पीडब्ल्यूडी श्रेणी से नर्सिंग अधिकारियों का एक भी पद भरने में विफल रहे। अब समिति ने सिफारिश की है कि इन पदों को भरा जाए। समिति ने पाया कि धन उपलब्ध होने के बावजूद पिछली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचाओं को सुविधा प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही। धन के ऑप्टिमम उपयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कमेटी को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि हेल्थ सर्विसेज यूनिट में दवाओं मेडिसिन इक्विपमेंट की भारी कमी थी। आमतौर पर कमी का कारण फंड की कमी होती है। लेकिन दिल्ली में यह कमी पूरी तरह लापरवाही और अनदेखी की वजह से था और इसका क्योंकि कोई सुपरविजन मॉनिटरिंग नहीं थी। खुद हमारी मुख्यमंत्री जी भी जब मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने कई सरप्राइज विजिट की थीं तो देखा कि भारी मात्रा में इक्विपमेंट्स गोडाउन में पड़े हैं। दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से खरीदी गई ये सारी चीजें गोडाउन में धूल फाक रही थीं लेकिन दिल्ली के काम नहीं आ रही थीं। मैं जब विपक्ष में था अध्यक्ष जी आपको भी ध्यान में होगा कि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती थी डीडीए जमीन नहीं देती, केंद्र जमीन नहीं देती। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि जमीन उपलब्ध होने के बावजूद सरकार ने इसका इस्तेमाल करने के लिए कभी कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। कभी हेल्थ सर्विस के लिए जमीन पर कब्जा में देरी, जमीन मिलने के बाद

निर्माण में देरी, निर्माण कार्य पूरा करने में देरी, अतिक्रमण हटाने में देरी। सभी स्टेज पर देरी ही देरी ये करते रहे और बेड रेशियो बेड पेशेंट रेशियो के कारण लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक और समस्या थी कि फंड लैप्स हो जाते हैं हर साल। तो प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते जिसके कारण वो फंड काम नहीं आता। वो लैप्स हो जाते हैं। पिछली सरकार सिर्फ झूठे वादे और विज्ञापन छपवाने में मस्त रही। लोगों के स्वास्थ्य सेवा से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे नहीं पता उनकी क्या दिक्कत थी। ऑडिट से ये भी पता लगता है कि केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम थीं अध्यक्ष जी मैं सदन को बताना चाहता हूं इसको ठीक से पढ़ें रिपोर्ट को जरूर कि जो सीएसएस की जितनी स्कीम थीं, आयुष्मान भारत हो, जननी सुरक्षा योजना हो, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री सुरक्षी माथित अभियान हो और एनएचएम के तहत लक्ष्य कार्यक्रम हो, मातृपूर्ण श्रेयन योजना हो, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो एक भी स्कीम ठीक से लागू नहीं की और इस नाकामी के कारण दिल्ली के गरीब लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और अब सरकार ने ये भरोसा दिलाया हमारी वर्तमान सरकार ने कि इस साल इसमें काफी सुधार किया जा रहा है। गंभीर चिंता के साथ समिति ने ये भी नोट किया है कि regulatory bodies का काम ठीक नहीं किया गया। झोलाछाप डॉक्टर बिना क्वालिफिकेशन वाले नर्सिंग पैरा मेडिकल स्टाफ नकली दवाओं के खतरे को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की जिससे लोगों की जाने खतरे में पड़ी हैं। सरकार ने इस मोर्चे पर स्थिति सुधारने का वादा किया है। कदम उठाना शुरू कर दिया है। अनेक चीजें हैं अध्यक्ष जी। एसडीजी थ्री, संयुक्त राष्ट्र संघ का 2030 का सभी उम्र के लोगों के लिए जो मातृशिशु होती है शिशु बीमारी से महामारी एड्स, टीबी, मलेरिया से लड़ने वाली मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुरक्षित करने के दवाओं को पहुंचाने में सुधार करने में प्रदूषण असुरक्षित पानी जैसे सभी विषयों पर जो दूर करने का वादा किया था इसे 2016 में अपनाया गया था जिसका लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का प्रयास अब सरकार ने कहा है। पिछली सरकार ने किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि ईडब्ल्यूएस स्कीम के बारे में ऑडिट में भी पाया गया कि सरकार ने जो गरीब लोगों को डीजीएचएस द्वारा पहचाने गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई मॉनिटर नहीं थी। कोई मुफ्त में इलाज नहीं हुआ। इस तरह से इन्होंने अफरातफरी फैला के रखी। ऑडिट रिपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कमेटी ने पाया कि आयुष संस्थानों की हालत भी बहुत खराब है। कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार को एलोपैथिक संस्थाओं के बराबर हमारे भारतीय चिकित्सा सिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। अंत में समिति ने ये नोट किया कि सरकार ने कमियों को ठीक करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाना शुरू किया है और जल्द कारवाई

का आश्वासन भी दिया है। समिति ने सिफारिश की है कि विभाग अपने आश्वासनों और समय सीमा का पालन सुनिश्चित करें और 31 जुलाई 2026 तक समिति की रिपोर्ट पर एक action taken report जमा करें। एटीआर में 30 जून, 2026 तक की प्रगति की स्थिति भी होनी चाहिए। इसके बाद विभाग की एटीआर जमा करने के वाले सत्र में पेश की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आठवीं विधानसभा के पीएससी की पहली रिपोर्ट विधानसभा में पेश करता हूं।[3] आपका बहुत-बहुत हृदय से आभार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः रिपोर्ट सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाए। अब समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण-तीन। माननीय सदस्य एवं अध्यक्ष पब्लिक अकाउंट्स कमेटी श्री अजय महावर जी लोकलेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री अजय महावरः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं पीएससी की यह दूसरी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। यह रिपोर्ट दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति का निष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में भारत के सीएजी की रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट संख्या एक पर आधारित है जिसे 25 फरवरी, 2025 को सदन के पटल पर रखा गया था। इस रिपोर्ट में दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर की गई निष्पादन लेखा परीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं। यह वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि को कवर करती है। अर्थात उस समय जब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया आबकारी विभाग के प्रभारी मंत्री थे। 2017 से 21 तक दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू थी और इस अवधि के लिए तात्कालिक सरकार ने 21-22 में एक नई आबकारी नीति लागू की जिसे बाद में उसी सरकार ने 31 अगस्त, 2022 को वापस ले लिया। अध्यक्ष महोदय एक तो मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीएजी ने जो नई आबकारी नीति 2020-21 की जांच की अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में यह रिपोर्ट दी है, चुंकि यह मामला सीबीआई और ईडी की जांच, अदालती कारवाई और विभागीय कार्यवाही का विषय था इसलिए समिति ने यह फैसला किया कि वह अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से सीएजी की टिप्पणियों, विभाग से मिले जवाब पर आधारित रखेगी। समिति की रिपोर्ट ना तो उन मामलों से प्रभावित होती है और ना ही उन्हें प्रभावित करनी चाहिए जो अदालती कार्यवाही या विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही का विषय है। यह एक स्वतंत्र रिपोर्ट है जो केवल सीएजी की रिपोर्ट विभाग के जवाब और समिति के निष्कर्षों पर आधारित है। सीएजी की रिपोर्ट में आबकारी विभाग का परफॉर्मेंस ऑडिट किया गया। इसमें भी अनेक मुद्दे शामिल किए गए। इसमें

[3] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23565 पर उपलब्ध।

आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली, लाइसेंसिंग नीति लाइसेंस जारी करना, मूल्य निर्धारण नीति, गुणवत्ता मानकों का अनुपालन, आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती से संबंधित मुद्दे, प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली, आबकारी नीति 2021-22 को लागू करना और उसका क्रियान्वयन। समिति ने अपनी बैठकों के इस मुद्दे को विस्तार से जांच की और मैं समिति के उन सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए काफी समय दिया और बहुमूल्य सुझाव दिए। समिति की पुरानी आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कई गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। नीति और आबकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए लाइसेंस देने में की गई अनियमितताओं से थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, होटलों, क्लबों, रेस्तराओं को फायदा पहुंचा, इससे अनुचित लाभ मिला, गुटबंदी और ब्रांड प्रमोशन जैसे अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को बढ़ावा मिला। जो भारतीय निर्मित विदेशी शराब है उसकी कीमतों के निर्धारण में भी पारदर्शिता की भारी कमी और मनमानी देखी गई और एल-1 लाइसेंस धारियों को अपने फायदे के लिए शराब की कीमतों में हेरफेर करने का मौका पिछली सरकार ने दिया। क्वालिटी कंट्रोल के उपाय बिल्कुल अपर्याप्त थे और कई मामलों में लाइसेंस धारियों ने जांच रिपोर्ट यानी टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध ही नहीं कराई और रिपोर्टों को ऐसी प्रयोगशालाओं से की गई जिनकी मान्यता ही प्राप्त नहीं थी। यह भी एक अचंभा हुआ है कमेटी को। राजस्व में होने वाली कमी का पता लगाने या तस्करी को रोकने में आबकारी खुफिया ब्यूरो और इनफोर्समेंट ब्रांच काफी हद तक अप्रभावी साबित हुए। बारकोड के माध्यम से शराब की एंड टू एंड ट्रैकिंग द्वारा भी कुशल विनिमय सुनिश्चित करने के लिए आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली ठीक से लागू नहीं की। इसमें कई उदाहरण भी हैं। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इस सदन को भी बताना चाहता हूं कि एक कंपनी है मेसर्स इंडो स्पिरिट वो थोक विक्रेता है। एक कंपनी है खाओ गली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, वो जोनल लाइसेंस धारी है। कमेटी ने पाया कि इनके बीच की शेयर धारिता निदेशक पद के संबंधों के जरिए जुड़ाव है। जबकि यह नियम के हिसाब से हो नहीं सकता था। खाओ गली रेस्टोरेंट जोन थ्री और जोन टू ने अपने शराब के स्टॉक का 45.26% इंडो स्पिरिट से खरीदा, जोकि नियम के खिलाफ था। यह थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के बीच संभावित वर्टिकल इंटीग्रेशन का संकेत देता है। निर्मताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं से जुड़े ऐसे अनेक मामले आए हैं। अच्छा शासन और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे में भी भारी अनियमितता है। ऑडिट रिपोर्ट के पृष्ठ 15 में बताया कि कई कैबिनेट फैसले कई फैसले कैबिनेट की मंजूरी या उपराज्यपाल से परामर्श के बिना ही लिए गए हैं। दिल्ली की आबकारी नीति 2021 की टेंडर प्रक्रिया के दौरान नौ शिकायतें मिली, जो विडर्स अयोग्य थे, बिना किसी जांच के 17 खुदरा शराब जोन आवंटित किए गए। इसके पीछे क्या मिलीभगत थी हमें नहीं पता।

यह कमेटी आगे इस पर अपनी रिपोर्ट रख रही है। सीएजी की रिपोर्ट और विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज और जानकारी के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि गलत आबकारी नीति को लागू करवाने में तात्कालिक माननीय उपमुख्यमंत्री, वित्त प्रभार मंत्री श्री मनीष सिसोदिया की भूमिका बेहद संदिग्ध और गंभीर साबित होती है। उनके फैसले से राजस्व को भारी नुकसान हुआ है जो सीएजी के आकलन के अनुसार लगभग 2002 करोड़ रूपये है। दिल्ली का नुकसान हुआ है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में बिना किसी उचित कारण के ऐसे बदलाव किए गए जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सामान्य कार्यालय प्रक्रियाओं, नियमों, दिशा निर्देशकों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और एक ऐसी नीति तैयार की गई जो मानो हवा में ही बना दी गई हो और बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए उस नीति को विभाग पर थोप दिया गया। यह तथ्य कि तात्कालिक सरकार ने एक साल के भीतर ही इस नीति को छोड़ा। क्योंकि इनको छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, इसे वापस लेना पड़ा, यह पूरी तरह से उनकी विफलता को साबित करता है। साथ ही जिसको वह वर्ल्ड क्लास पॉलिसी बता रहे थे। साथ ही यह उनकी दूरदर्शिता और योजना की कमी को भी उजागर करता है और उनके दुर्भावनापूर्ण इरादों को भी बेनकाब करता है। श्री मनीष सिसोदिया ने ऐसे बहुत निर्णय लिए जो सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी के बिना ही लिए गए और उसका कारण क्या थे ये तो वही जानते होंगे, क्योंकि हमें तो सीधे संदेह के घेरे में लाने के लिए वो विवश करते हैं। कई चीजें बता सकते हैं। बिना किसी औचित्य क्या, कारण के विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से हटकर निर्णय लेना, निर्धारित तय समय के भीतर लाइसेंस शुल्क का भुगतान ना करने की स्थिति में लाइसेंस धारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाही के संबंध में ढील देना, लाइसेंस शुल्क की छूट में कमी करना, एयरपोर्ट जोन के मामले में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की वापसी करना, ये सारे ऐसे मामले हैं जो बहुत ही गंभीर सवाल उठाते हैं अध्यक्ष महोदय चूंकि यह मामला पहले से ही माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसलिए समिति किसी भी कार्यवाही के अनुशंसा का फैसला इस सदन पर छोड़ती है तथापि इस समिति इस बात से पूर्णतः आश्वस्त है कि श्री मनीष सिसोदिया के व्यक्तिगत निर्णयों के कारण सरकार को 2 हजार करोड़ से ज्यादा की राजस्व हानि हुई है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस रिपोर्ट का अवलोकन जरूर करें जो इस तथ्य को बिना किसी संदेह के सिद्ध करती है। अंत में अध्यक्ष जी मैं आपके अनुमति से पीएससी की ये दूसरी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।[4] आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

[4] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23566 पर उपलब्ध।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण- चार, माननीय सदस्य एवं अध्यक्ष पब्लिक अकाउंट्स कमेटी श्री अजय महावर, लोक लेखा समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री अजय कुमार महावर: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, प्रदूषण की इस रिपोर्ट पर मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पीएससी की तीसरी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करता हूं। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदर्शन की रोकथाम और समन के प्रदर्शन ऑडिट पर सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। समिति ने विस्तृत विचार विमर्श किया और प्रतिनिधियों को भी लिखित उत्तर प्रस्तुत करने तथा बैठकों में अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर दिया अध्यक्ष जी, समिति परिवहन और पर्यावरण विभाग एनसीटी दिल्ली सरकार के अधिकारियों, महालेखाकार ऑडिट, अतिरिक्त उप सीएजी अपनी बैठकों के दौरान तथा रिपोर्ट तैयार करने में विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए सहयोग के प्रति भी कमेटी आभार प्रकट करती है। समिति ने पाया कि ऑडिट में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित योजना निगरानी और लागू करने के तंत्र में कई व्यवस्थागत कमियां आई हैं। जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। उसमें वायु गुणवत्ता, निगरानी केंद्रों के स्थान पर कामकाज में कमियां, निर्धारित प्रदूषकों की अधूरी निगरानी, उत्सर्जन स्रोतों पर विश्वसनीय डाटा की कमी और नीति बनाने के लिए अपर्याप्त वैज्ञानिक जानकारी शामिल है। समिति ने आगे यह भी पाया कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अभी भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बसों की कमी, सीमित रूट कवरेज, अंतिम मिल तक कनेक्टिविटी की कमी, रूट को तर्कसंगत बनाने, वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों को लागू करने में देरी के मामले, इन कमियों की वजह से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की पहुंच, विश्वसनीयता पर बुरा असर डाला और हो सकता है इसी से निजी वाहनों पर निर्भरता बढ़ी हो और यह प्रदूषण के लिए घातक सिद्ध हुई हो। समिति ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के नियमों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण कमियां पाई। जिसमें प्रदूषण जांच केंद्रों की अपर्याप्त कवरेज और प्रदूषण नियंत्रण पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता, उत्सर्जन जांच की कमजोर निगरानी, आधुनिक उत्सर्जन निगरानी तकनीकों को लागू करने में धीमी प्रगति, ये सभी विषय शामिल हैं। बड़ी संख्या में जीवन अवधि पूरी कर चुके वाहन का बने रहना उन्हें कबाड़ में

बदलने और पंजीकरण रद्द करने में सीमित प्रगति के वाहनों से होने वाले प्रदूषण समस्या को और गंभीर बनाया। पिछले वर्षों में नीतिगत उपाय जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, उत्सर्जन जांच प्रणाली को मजबूत करना। शहरी यातायात प्रबंधन के उपाय अपनाना, ऐसे पहलुओं को लागू करने में अक्सर पिछली सरकार का काम धीमा हुआ और बिखरा हुआ था। कई लागू करने वाली एजेंसियों के बीच में समन्वय की भारी कमी भी इन उपायों की प्रभावशीलता को कम कर दिया है, सीमित कर दिया है। समिति का सुविचारित मत है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक और स्मृद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें मजबूत निगरानी प्रणाली, नियमों को शक्ति से लागू करने का तंत्र, टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन विस्तार, स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देना और बेहतर शहरी यातायात प्रबंधन शामिल है। इसलिए समिति संबंधित विभागों, एजेंसियों को इस आवश्यकता पर जोर देती है कि इस रिपोर्ट पर दी गई सिफ़ारिशों को समय सीमा के भीतर लागू करें, त्वरित करें और समन्वित कार्रवाई करें। समिति को उम्मीद है कि सरकार ऑडिट में उजागर की गई कमियों को दूर करेगी और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करेगी ताकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और शहरी गतिशीलता में लगातार सुधार हासिल किया जा सके। विभाग को अपनी समिति की सिफारिशों पर अपनी की गई कार्यवाही की रिपोर्ट यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए और उसे 31.12.2026 तक की स्थिति के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। की गई कारवाई की रिपोर्ट 31 जनवरी 2027 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आठवीं विधानसभा की पीएससी की यह तीसरी रिपोर्ट सदन के समक्ष विधानसभा में प्रस्तुत करता हूं।[5] धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण-पांच। माननीय सदस्य एवं अध्यक्ष, प्रिविलेज कमेटी विशेष अधिकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत जी विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन, अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रधुम्न सिंह राजपूत: अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से विशेष अधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन अंतिम रिपोर्ट आपके सामने रखूं उससे पहले मैं तथ्य रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, समिति ने उनको तीन बार बुलाया जिसमें से वह दो बार अनुपस्थित रहे, बचते रहे और तीसरी बार जब आए वो तो उसके बाद उनका संतोषजनक जवाब नहीं था, उनका आचरण जैसे पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं उसके अनुसार नहीं था। बाद में उन्होंने उस आचरण के लिए कमेटी के समक्ष माफी भी मांगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधानसभा एक ऐतिहासिक इसका गौरवशाली यात्रा है और किसी भी पार्टी के नेता को यह अधिकार नहीं है कि

[5] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23567 पर उपलब्ध।

अपनी पार्टी के फायदे के लिए और इस ऐतिहासिक भवन के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करें, यह उन्होंने करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मीडिया में भी बड़ा दुष्प्रचार किया। मीडिया में कहा गया कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमसे सवाल किए जा रहे हैं, इनको हमको बुलाना है तो हमारी सलाह लेनी चाहिए कि जो दिल्ली के अंदर पानी की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, पोल्यूशन की दिक्कत है, उसमें हमारा मार्गदर्शन लेना चाहिए क्योंकि हमें इतने सालों का अनुभव है। मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि अगर इतने सालों का अनुभव था तो दिल्ली का बेड़ा गर्क करके क्यों रख दिया तुमने? दिल्ली को 20 साल पीछे करके तुमने रख दिया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सभी अपने साथियों का, अधिकारियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं उन्होंने रिपोर्ट बनाने में सहयोग किया। अध्यक्ष महोदय मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो इन्होंने फांसीघर के बारे में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, देश की जनता को दिल्ली की जनता को गुमराह किया और वह सच आप लाने का प्रयास कर रहे हैं सामने उसके लिए भी मैं आपका आभार धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विशेष अधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन अंतरिम रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करता हूं।[6] धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही अब 1.45 तक के लिए स्थगित की जाती है

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 1.45 तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 1:47 बजे पुनः समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए

माननीय अध्यक्ष: आप कुछ कहना चाहते हैं। जी।

श्री कुलदीप सोलंकी: माननीय अध्यक्ष जी। पिछली 18 तारीख बुधवार को पालम विधानसभा, साध नगर, पालम कॉलोनी की मार्केट में एक आग की बहुत भयावह दुर्घटना हुई जिसमें एक ही परिवार के नौ सदस्य उस अग्नि की चपेट में आए और मृत्यु लोक को चले गए। दुर्घटना भयावह थी। मैं वहीं रहा सारा दिन।

---

[6] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23568 पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष: एक मिनिट सोलंकी जी। आप अपनी बात कहे उससे पहले दो मिनट बैठिये आप । माननीय सदस्यगण, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों और विपक्ष के नेता द्वारा सदन के बाहर किए जा रहे प्रदर्शन की कड़ी निंदा करता हूँ। सदन का बहिष्कार करना और कार्यवाही में भाग ना लेना सदन की गरिमा और संसदीय मर्यादा के पूर्णतः के खिलाफ़ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन ही वह स्थान हैं जहाँ चर्चा और संवाद होना चाहिए। लेकिन विपक्ष द्वारा बजट सत्र से दूरी बनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेषकर इस समय जब दिल्ली का बजट पेश किया जा रहा है, विपक्ष की भागीदारी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्चा छोड़कर बाहर प्रदर्शन करना, स्थापित संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है। यह अत्यंत खेदजनक है कि पिछले सत्र में जब गुरुओं की बेअदबी का गंभीर मुद्दा उठा था तब से नेता, प्रतिपक्ष सदन में नहीं आयी है। यानि की पिछले बैठकों में भी नेता, विपक्ष सदन से गायब रही और अब भी लगातार अनुपस्थित है, किसी भी बहाने के साथ। इस प्रकार सदन की कार्यवाही में भाग न लेना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डालना संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करने जैसा है।

आज सदन के पटल पर कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की गई हैं जिन पर विपक्ष को अपना पक्ष रखना चाहिए और चर्चा में भाग लेना चाहिए। विशेषकर जब दिल्ली का बजट पेश हो रहा है तब विपक्ष की उपस्थिति अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेरा ये कहना है कि संसदीय परंपराओं के विरुद्ध जाकर सदन की गरिमा के साथ उद्दंडता करना और बार बार चेयर की अवमानना करना अत्यंत निंदनीय है। माननीय सदस्यगण आज अभी मेरे पास जो घटना पालम क्षेत्र में हुई है उससे फायर इंसिडेंट जो हुआ है उस पर मंत्री श्री आशीष सूद जी का भी स्टेटमेंट के लिए मुझे उनका अनुरोध प्राप्त हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण एक दुर्घटना जो इस सदन में चर्चा के लिए स्वंय सरकार ने यहाँ पर आवेदन दिया है और उसमें विपक्ष सड़क पर तो बात करता है फायर इंसिडेंट की लेकिन सदन के पटल पर जब बात हो रही है और मंत्री उस पर खुद कह रहे हैं कि मैं इसपर स्टेटमेंट करना चाहता हूँ, तब उनसे सवाल पूछने के लिए उस पर अपनी बात कहने के लिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। ये इन, क्योंकि इस तरह का व्यवहार सर्वथा निंदनीय है कि सदन के पटल पर बात ना करना और सदन के अंदर जब आकर के फिर शोरगुल करना, सदन को डिस्टर्ब करना, चेयर की अवमानना करना, सदन की अवमानना करना और जो सदन में

घटित होता है, बाहर जाकर उसके विपरीत बोलना, यानि की गुमराह करना जो अपने आप में एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है। ये लगातार हो रहा है, लगातार इस तरह की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। ये बहुत ही कष्टदायक है। मैं फिर इनसे ये अपील करता हूँ कि पालम के फायर इंसिडेंट पर यहाँ पर मंत्री जी का स्टेटमेंट होगा। बाकी सदस्यों को भी मैं मौका दे रहा हूँ कि वो इस पर अपनी बात कहें। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि वो सदन में आएं और दिल्ली की जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उसको वो पूरा करे और सरकार से पूछे, जो भी कुछ पूछना है, जो भी कुछ कहना है, हम सदन में उनको पूरा मौका देंगे हर मुददे पर। कोई जनहित का मुद्दा वो उठाना चाहते हैं उसके लिए हम उनको फिर अपील करते हैं वो सदन में आएं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। लेकिन जिम्मेदारी से भागना, चर्चा में भाग ना लेना, सदन को चलने ना देना, मंत्री जवाब दे रहे उन जवाब पर कोई प्रश्न ना पूछना ये निंदनीय है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना है, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। अब मैं अभी 1 मिनट बस बस अब इसमें सोलंकी जी।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः एक बार ये विषय हो जाए फिर करवा लेंगे बात।

श्री कुलदीप सोलंकीः अध्यक्ष जी आपने भी संज्ञान लिया सवेरे इस बात को लेकर। ये राजेंद्र कश्यप जी का परिवार मार्केट में रहता था, नीचे उनकी दुकान और ऊपर उनकी रिहायश थी, मार्केट असोसिएशन के प्रधान भी हैं और दुर्घटना हुई। अब कैसे हुई वो तो एक जांच का विषय है। लेकिन एक ही परिवार के नौ सदस्यों का चले जाना दुखद घटना हैं। और विपक्ष के लोग जैसे वहाँ क्षेत्र में भी उन्होंने जिस तरह की हरकतें की ये बड़ी निंदनीय है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, अखबारों के माध्यम से भी देखा होगा। तो मैं] दिल्ली की जनता भी चाहती है, पालम भी चाहता है और विधानसभा भी चाहती है कि भई हमारे मंत्री जी इसपे वक्तव्य देकर अपनी बात रखें, मेरा उनसे ये निवेदन है ।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री श्री आशीष सूद जी।

माननीय मंत्री का वक्तव्य(नियम-270)

श्री आशीष सूद, माननीय गृह एवं शिक्षा मंत्रीः बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी आपका। आपने दिल्ली के एक बहुत ही ज्वलंत, बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखदायी विषय पर मुझे अपना बात कहने का और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो दिल्ली के इनफ्रास्ट्रक्चर के हर सेगमेंट में हो रहे विषय और जिस प्रकार से दृढ प्रशासनिक कदमों से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रही है, वो विषय यहाँ सदन में रखने का आपने अवसर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं मैं इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। इस घटना में जिन लोगों की जान गई है उनकी सद्गति की प्रार्थना करता हूँ और जिन लोगों ने अपने नियर एंड डीयर्स को अपने आप परिजनों को खोया है उनके साथ मैं इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूँ। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। इससे पहले कि मैं इस घटनाक्रम पर क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात कहूं। मैं यहाँ सदन के पटल पर इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूँ कि जिस दिन वो घटना घटी पूरी सरकार, पूरी जिम्मेदारी के साथ उस घटना के पीड़ितों के साथ रही। घटना की रिपोर्ट आते ही 2 घंटे से भी कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैजिस्टीरियल इन्क्वाइरी की बात कही, मृतकों के लिए, घायलों के लिए एक्सक्रेशिया की घोषणा की गई। पोस्टमॉर्टम समय पर हो उनके परिजनों को उनके शव मिल जाए इन सबके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं और उन्होंने मुझे और बाकी लोगों को निर्देश दिया। हम सब उस विषय में जागरूकता के साथ काम कर रहे थे, परिवार के दुख की घड़ी में उनके साथ थे। मैं स्वयं लगभग डेढ़-पोने घंटे तक भाई कुलदीप जी के साथ मंगलापुरी श्मशान में मृतक परिवार के साथ उनका दुख साझा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहाँ था। भाई कुलदीप वहाँ पूरा दिन, परिवार का दुख साझा करने के लिए थे। ये बातें मैंने इसलिए यहाँ कही। देखिए जान किसी की भी जाए बहुत पीड़ादायक है, उससे ज्यादा पीड़ा आदरणीय अध्यक्ष जी तब होती है जब जान जाने पर लाशों के ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया जाता है, गिद्ध राजनीति की जाती है, वल्चर पॉलिटिक्स की जाती है, सबसे ज्यादा दुखदायी वो क्षण होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी इस संदर्भ में पुलिस की जांच चल रही है फायर की जांच चल रही है और उस पूरे घटनाक्रम में मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी पढ़ूंगा मगर उससे पहले जैसा आपने कहा इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है और विपक्ष बाहर हैं ये उनके ऐटिट्यूड को दिखाता है। उन्हें मालूम था उन्हें मालूम था कि यहाँ पर यहाँ पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष के पिछले 11 साल का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी उभर कर सामने आएगा। इसलिए

उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार न करते हुए सदन से बाहर रहना ही उपयुक्त समझा। मगर उनके ऐटिट्यूड को मैं आपके सामने और इस पवित्र सदन में जिम्मेदारी से एक संवैधानिक पद पर होते हुए जिम्मेदारी से मैं दिल्ली की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी दिल्ली में जनवरी 2018 में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी। अध्यक्षजी ऐसा रहा कि जैसे एक पुरानी घटना घटी थी दिल्ली में। एक मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद वो व्यक्ति छूट गया और अगले दिन अखबार ने एक बड़ी हेडलाइन छापी 'नो वन किल्ड जैसिका'। इस प्रकार की घटनाओं, इस प्रकार का आचरण विपक्ष का है। जनवरी 2018 में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी आग लगी, 17 लोगों की जान गई उस समय की सरकार ने इसकी जिम्मेदारी एमसीडी के लाइसेंसिंग विभाग पर डाल दी, ये कहा कि ये आग लाइसेंसिंग विभाग के कारण लगी है। उस समय एमसीडी में भाजपा थी, सभी के देखने के लिए अखबार में उसके तथ्य उपलब्ध है । उसके बाद फरवरी 2019 में लगभग शायद 12 फरवरी 2019 को करोल बाग में अर्पित होटल में आग लगी । फिर 17 लोगों की मौत हुई और एनओसी प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार है ऐसा कहकर एमसीडी पर आरोप लगा कर। उस जिम्मेदारी से उस समय की सरकार ने बचने का प्रयास किया। ''आप अटैक्स बीजेपी रूल्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन'', उस समय के मंत्री थे, उस समय चीफ स्पोक्सपर्सन थे, उन्होंने कहा एनडीएमसी के साथ मिलकर परमिशन गलत दी गई।

अनाज मंडी में 2019 में आग लगी, 43 लोगों की जान गई। कहा गया स्पेशल एरिया रिडेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया गया था इसलिए आग लग गई, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अखबार भरे पड़े थे। ऐटिट्यूड है।

सबसे बड़ी बात तो अध्यक्ष जी ये हुई, मई 2022 में मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी, 27 लोगों की जान गई, 27 लोगों की जान गई। यहाँ सामने अगर नेता-प्रतिपक्ष बैठी होतीं तो मैं उन्हें याद दिलाता। नेता- प्रतिपक्ष जी ने और आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता- दुर्गेश पाठक ने यह कहा कि यह बिल्डिंग बीजेपी के नेता की है, आग लग गई, बीजेपी जिम्मेदार है इस आग की। 27 लोगों की मौत का जिम्मा लेने से दिल्ली की सरकार ने अब पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत समझी।

अध्यक्ष जी, हम वल्चर पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं, वल्चर पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं। हम में से किसी ने यह नहीं कहा। भाई कुलदीप यहाँ बैठे हैं। हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि जिसके घर पर आग लगी है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। भई नौ लोगों

की जान गई हैं। ये जान क्यों गई, इसकी जांच होनी चाहिए। फायर ने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी, अध्यक्ष जी मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, "only one single staircase from the ground to terrace floor which was not accessible from outside due to the intense heats, smoke and flames as well the material involved such as मैं माननीय सदस्यों का ध्यान चाहता हूँ और आप के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ, smokes and flame as well as the material involved such as garments, cosmetics, thinner, nail polish, perfume which was highly inflammable which was highly inflammable" उस बिल्डिंग की बेसमेंट में highly inflammable material saved था। मकान के अंदर से सीढ़ी ऊपर गयी हुई थी, कोई बाहर से सीढ़ी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक शटर था, आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शटर उठा नहीं। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहा आम आदमी पार्टी के नेता की बिल्डिंग थी, उसमें highly inflammable material saved था। दिल्ली की सरकार में किसी ने ये ब्लेम पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पहले 2 घंटे के अंदर मैजिस्टीरियल इन्क्वाइरी की घोषणा की। ex gratia की घोषणा की। भाई कुलदीप पूरा दिन वहाँ दुख बटाते हुए रहें। दो घंटे तक मैं श्मशान भूमि पर रहा। हमारे कार्यकर्ता मृतक परिवार के पोस्ट मार्टम में सहयोग करते रहें। हमने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता की बेसमेंट में inflammable material था। ये passing the buck करने का तरीका है, ये ऐटिट्यूड आम आदमी पार्टी की सरकार में चलता होगा, श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार में आगे से जिम्मेदारी लेकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। Mundka fire, "aap blames, illegal construction."

और आज जिन लोगों को बड़ी- बड़ी बातें याद आ रही हैं उनका भी नाम लेकर बताऊँगा आपके सामने अध्यक्ष जी। अलीपुर की पेंट फैक्टरी में आग लगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन को टिप्पणी करनी पड़ी, नेशनल ह्यूमन राइट्स को कमिशन को टिप्पणी करनी पड़ी। मगर इस बार बड़ी अजीब घटना हुई, दिल्ली की सरकार ने नगर निगम को दोषी नहीं बताया साहब क्योंकि नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर थीं। नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर थीं इसलिए उसके संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने, उस सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की।

और ईस्ट दिल्ली के चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में आग लगी, बच्चे जलकर मर गए, बच्चे जलकर मर गए और दिल्ली के मिनिस्टर जो आज बड़ी- बड़ी बातें कहते हैं, confronted

on infants death “Delhi Minister Saurabh Bhardwaj blames media, blames media” कि मीडिया ने इसको out of the proportion blow किया है।

अध्यक्ष जी, आपके सामने ये सब बातें मैंने इसलिए बताई हैं कि यह पिछली सरकार का और आज, जो आज इससे नजर चुराकर भाग रहे हैं उनके दृष्टिकोण को दिखलाता है और उनके कृत्यों को दिखलाता है। सारी दिल्ली जानती है, सारा देश जानता है, शहर आगे बढ़ रहा है, शहर में आबादी बढ़ रही है, शहर में आबादी बढ़ रही है। सबको पता है मिक्स लैंड यूज़ एरिया है। फायर के नियम उस रेजिडेंशियल एरिया में लागू नहीं होते हैं। ग्यारह साल लग गए किसी ने उन नियमों के बारे में परिवर्तन करने का, फायर ब्रिगेड के काम को, फाइर फाइटिंग के काम को प्रिकॉशनरी कामों के लिए कोई चर्चा दिल्ली के सदन में नहीं हुई, कुछ भी कार्रवाई इसमें नहीं हुई। और तो और अध्यक्ष जी, आपको यह जानकर हैरानी होगी, सबको पता है शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, पॉप्पुलेशन की डेनसिटी बढ़ रही है, अन ऑथोराइजड कॉलोनियां बनी हुई हैं उनकी रेगुलराइजेशन पिछली सरकारों ने किया नहीं, उनके अंदर जाने के लिए फायर ब्रिगेड्स की कमी है। फायर के.. फायर टेंडर उसमें जा नहीं सकता है। कोई ऐसी व्यवस्था पिछले 11 सालों में खड़ी करने का प्रयास नहीं किया गया जिससे उन को सुदृढ़ किया जाना था। और ये मैं तथ्यात्मक रूप से अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूँ। 2015-16 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो केवल 4 करोड़ 72 लाख रूपये दिल्ली की फायर ब्रिगेड के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कोई फायर टेंडर खरीदने के लिए, पाइप खरीदने के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। 2016-17 में केवल 8 करोड़ रूपये खर्च किए गए, 2016-17 में केवल 8 करोड़ रूपये खर्च किए गए। 2021-22 में केवल 20 करोड़ रूपये खर्च किए गए। 2018-19 में 5.52 करोड़, 5 करोड़ रूपये। इतने कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इतने से कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ दिल्ली की फायर व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा था।

और जो आज, आज passing the buck और passing the blame करने का काम कर रहे हैं उसके विपरीत, उसके विपरीत इस वर्ष हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली फायर सर्विस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 180 करोड़ रूपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है और 180 करोड़ में से काफी सारा पैसा अभी तक खर्च भी किया जा चुका है। नए फायर टेंडर लेने के लिए, नई मशीनें लेने के लिए, फायर के लोगों को लड़ने के

लिए बढ़िया इक्विपमेंट दिलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार सरकार निवेश कर रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

और, और अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ ये जितनी फायर मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, जितनी फायर मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, 2016 में नरेला में, 2017 में आनंद पर्वत पे, 2018 में बवाना में, 2019 में अर्पित होटल- करोल बाग, फिर 2019 में अनाज मंडी- सदर बाजार, 2020 में उद्योग विहार, 2022 में मुंडका और 2024 में बेबी केयर हॉस्पिटल- विवेक विहार, इसमें से केवल 2019 में अर्पित होटल पर और 2022 में मुंडका पर मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी ऑर्डर हुई और 2022 की मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी कहां है, फायर के पास उसकी क्या फाइन्डिंग है, आज तक उस सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है।

और, और जो बड़ा शोर मचा रहा अध्यक्ष जी कि, कि हमने, जैसे एक वर्ष में लापरवाही के कारण यह हादसा हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको मैं ये दो बातें और बताना चाहता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर और सरकार की जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड को मजबूत करने की मैंने आपके समक्ष रखी है। अध्यक्ष जी, आपको जानकर हैरानी होगी, मैं आपके माध्यम से, आप के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ 1969 में दिल्ली फायर सर्विस को एक वायरलेस सेवा दी गई थी कि आपस में कम्यूनिकेशन के लिए, अध्यक्ष जी, 1969 को, और आज उसकी स्थिति क्या है? आज एक वायरलेस पर फायर होने के बाद, फायर होने के बाद वायरलेस पर फायर इंजन को निकाल दिया जाता है। उसके बाद फायर इंजन वहाँ से निकला और फायर की स्थान तक जा रहा है, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। फायर के स्थान पर पहुँच गया, वहाँ उसको कुछ और चाहिए तो वापस जाने के लिए कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। एक फायर में चार कोनों से चार फायरमैन चढ़े हुए हैं वो बिचारे अपना फ़ोन निकाल-निकाल कर बात करते हैं, अपने फ़ोन से कम्यूनिकेशन की कोशिश करते हैं, आग बुझाते समय फ़ोन गीले हो जाते हैं, संपर्क नहीं होता, संपर्क नहीं होता। 11 साल लग गए पिछली सरकार को फायर ब्रिगेड को लड़ाई लड़ने के लिए, फायर ब्रिगेड को फायर बुझाने के लिए। एक फायर का एक-एक वायरलेस का इंटरनल कम्यूनिकेशन नेटवर्क नहीं दे पाए। यह मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार है जिसने पिछले छह महीने में आगे बढ़कर प्रयास पूर्वक उसको नए फायर ब्रिगेड को नया कमांड सेंटर और नया कम्यूनिकेशन नेटवर्क देने का काम किया है। आप कल्पना करिए एक बिल्डिंग में चार कोनों से अलग-अलग

सीढ़ी से फायर के साथी चढ़े हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। मेरे यहाँ क्या दिक्कत हो रही है बता नहीं सकते। उसको फायर बुझाते समय जेब से फ़ोन निकालकर बताना पड़ेगा। अगर उसका फ़ोन गीला हो गया तो चारों तरफ ब्लैकआउट है। उसको अगर अपने फायर के हेडक्वार्टर को दुबारा कुछ बताना है बताने के लिए कोई नेटवर्क नहीं है। 11 साल का ये दिल्ली को प्रशासन देकर गए हैं और अध्यक्ष जी सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है अध्यक्ष जी। आप सबने सुना है मैं क्यों गीद्ध राजनीति कह रहा हूँ, मैं क्यों वल्चर पॉलिटिक्स कह रहा हूँ। मैं इसलिए वल्चर पॉलिटिक्स कह रहा हूँ आप सब सुन रहे है, आप सब सुन रहे है Bronto Skylift नहीं चली Bronto Skylift नहीं चली Bronto Skylift नहीं चली हाँ Bronto Skylift नहीं चली। अध्यक्ष जी, आपके मार्फत से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ। 2019 में जब फरवरी में करोल बाग में फायर हुआ। करोल बाग में फायर हुआ तो एक इंटरनल कमिटी बनी। उस इंटरनल कमेटी ने जांच करके ये जानकारी देनी थी, ये सुझाव देने थे कि कैसे फायर ब्रिगेड को मॉडर्नाइज किया जाए। अध्यक्ष जी मेरे पास ये कागज है, मंत्री के दस्तखत के साथ कागज है। 2019 की फायर के बाद 18/02/2020 को उसकी रिकमेन्डेशन आई। फरवरी 2019 के बाद फरवरी 2020 में 1 साल बाद तो ये सरकार जागी और रिकमेन्डेशन दी। रिकमेन्डेशन देकर कहा तीन फेज में, तीन फेज में पहले फेज में 252 करोड़, दूसरे फेज में 165 करोड़ और तीसरे फेज में 208 करोड़ रुपये की मशीनें खरीदी जाएं, मॉडर्नाइजेशन किया जाए। पहले फेस के 252 करोड़ रुपये के लिए मेट्रो के साथ संपर्क साधा गया। ये ब्रांटो मशीन खरीदने के लिए बात की गई। यह ब्रांटो कंपनी का नाम है अध्यक्ष जी। स्काई एक स्काई लिफ्ट है यूं करके खुलती हुई ऊपर जाती है। ब्रांटो एक विदेशी कंपनी है, एक विदेशी कंपनी की लिफ्ट खरीदी गई। खरीदने की रिकमेंडेशन हुई और डीएमआरसी को उसके लिए नियुक्त किया गया और अध्यक्ष जी, ये मैं ये दिखा रहा हूँ, ये साइन किया हुआ है ये। ये तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन के साइन हैं 197 करोड़ रुपये दिए 20/05/2022 को। अभी थोड़े दिन पहले वो मंत्री जी जो अपने को आजकल बेरोजगार नेता कहते हैं वो बार-बार कह रहे थे मैं फाइल में देख के आया हूँ, मैं फाइल में लिख कर गया था कि ये चीज़ नहीं खरीदी जानी। ये फाइल नहीं उन्हें याद आती कि लिखके 3 साल बाद मंत्री ने 197 करोड़ दिए। बात यहीं नहीं रुकी अध्यक्ष जी, 197 करोड़ देने के बाद यूरो और भारत के रुपये में करेंसी का चेंज आ गया। करंसी के एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आ गया। 2025 फरवरी में सरकार चली गई मगर ब्रांटो मशीन के लिए सरकार उस एक्सचेंज रेट के डिफरेंस को भी पूरा नहीं कर पाई इसलिए

ब्रांटो मशीन नहीं आ पाई। बाद में सरकार को आने के बाद मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सरकार को उसी एनजीटी से हमें परमिशन हुई। उसको चेसी बदलकर ब्रांटो मशीन नई चेसी पर लगाई और चल रहा है उसका समाधान आज श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार उन सब गड्ढों को भर के समाधान करने के लिए लगी हुई है। सारा देश जानता है, सारा शहर जानता है शहर में आबादी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है, गलियों में आने जाने के रास्ते बढ़ रहे हैं बताइए किसको नहीं पता ये मगर पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। आज ब्रांटो मशीन नहीं चल रही है, ब्रांटो मशीन नहीं चल रही है, ब्रांटो मशीन नहीं चल रही। अरे भाई, बेरोजगार नेताओं तुम्हारे कारण ब्रांटो मशीन 5 साल 2019 से 2025 फरवरी 6 साल में ब्रांटो मशीन नहीं खरीदी गई। सरकार की रिपोर्ट तीन हिस्सों में पैसा खर्चने की ब्रांटो मशीन नहीं खरीदी गई। फायर विभाग ऐसा विभाग है जिसमे रोज़ के रोज़ हमें बहुत सारी बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं मॉडर्नाइजेशन करने के लिए with the ever increasing population of the city, we need to innovate, we need to invest in new infrastructure जो मैं जैसा मैंने बताया, पहले साल में हमने हमारे आते ही बजट बना हमने तुरंत कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें बढ़ाया। बहुत सारी मशीनरी का बहुत सारी मशीनरी का टैस्ट की गई और उसकी खरीद का काम अभी आगे चल रहा है। मैं अध्यक्ष जी अंत में यह बताना चाहता हूँ, यह तो हुआ पिछले सालों में मगर इस 1 साल के अल्पकाल में, इस 1 साल के अल्पकाल में फायर को मॉडर्नाइज करने के लिए और दिल्ली को बचाने के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने क्या किया मैं ये भी बताना चाहता हूं और ये बताने से पहले मैं जिम्मेदारी से फिर कहना चाहता हूँ हम किसी पर दोष नहीं दे रहे हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ है, हम मृतक परिवार के साथ है, हम में से कोई ये नहीं कहने जा रहा है जैसे मुंडका के फायर मैं कह दिया कि बीजेपी के नेता की बिल्डिंग थी जो कभी साबित नहीं हुआ। ये डिक्लेयर्ड आम आदमी पार्टी का नेता है जिसकी बेसमेंट में ज्वलनशील मटीरियल था, ये फायर विभाग की रिपोर्ट है जो उन्होंने दिल्ली पुलिस को दी है जिस पर आगे फॉरेन्सिक की जांच चल रही है। मगर हम ये passing the buck नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम मृतक परिवार के साथ है। राजेंद्र को जफ्फी डाल कर उसको अपने सीने से लगाकर मैंने उनका दुख बांटने की चेष्टा की है मगर ऐसे मौके पर बताइए ना जिसके घर के 9 बच्चे चले जाएं उसको क्या सांत्वना दे सकते हैं आप। किसके पास शब्द हैं वो सांत्वना देने के लिए। हम तो केवल उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। एक ओर ब्रांटो मशीन जो 6 साल जिसके ऊपर ये बैठे रहे मॉडर्नाइजेशन

के लिए। मैंने बताया एक वर्ष में 5 करोड़ का capex, एक वर्ष में 3 करोड़ का capex, एक वर्ष में 18 करोड़ का capex 2 करोड़ से ऊपर की फायर की आबादी जो पुराने सेन्सस के आधार पर है। Ever increasing population तंग गलियां। क्या हममें से कौन नहीं जानता। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रात को कोई दुर्घटना घट जाए तो फायर इंजिन नहीं घुस सकता। मैं बताता हूँ हमारी सरकार ने क्या-क्या किया मगर उससे पहले अध्यक्ष जी ये जो दुष्प्रचार है उसके बारे में आज, पिछले 5-7 दिन में किस प्रकार से रिपोर्ट किया गया है। Short circuit, stock piles and a fatal trap upstairs. How fire turn Delhi building into a death trap? Garments, cosmetics, fueled blaze. This is not my or government report but it is the headline of the leading newspaper 'Times of India'. मैं नहीं कह रहा हूँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 'Times of India', "the blaze broke out around 07:00 A.M. at a Four Storey building at WZ Block of Palam, Ram Chowk market and quickly engulfed the structure fed by large stock piles of garments, cosmetic items stored in the lower floor, the basement ground and first floor of house, the cloth and a cosmetic showroom while the family lived on the second floor." Again I am quoting the newspaper. "An initial probe suggested a short circuit possibly linked to an electrical fault such as running water motor may have sparked the fire. The police may get the exact cause of fire which is under investigation." हिंदी मीडिया ने बताया 30 दमकल गाड़ियां तैनात की गई। उन्होंने डिप्टी फायर ऑफिसर के उस बयान को प्रमुखता दी जिसमें कहा गया साध नगर की संकरी गलियों के बावजूद विभाग भीषण गर्मी और धुएं के बीच ऊपरी मंजिल से 9 लोगों को बाहर निकालने में सफल रहा है। एनडीआरएफ, सर एनडीआरएफ और वायु सेना पुलिस के आगमन का उल्लेख हुआ। उनके हस्तक्षेप और उच्च स्तरीय प्रयासों को दिखाया गया और बहुत सशक्त कदम के रूप में अखबारों ने त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई को एक सक्रिय प्रोऐक्टिव रूप के रूप में अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल वित्तीय घोषणाओं- वयस्कों के लिए 10 लाख और नाबालिगों के लिए 5 लाख, ये सब चीजें इंडिपेंडेंटली दिल्ली के मीडिया ने रिपोर्ट की हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं अपनी बात के अंत में हमारी सरकार ने क्या किया यह पिछले 11 साल जो कुशासन के 11 साल हैं जिसमें हर घटना पर दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का काम किया। मृतकों की जान को नजरंदाज करते हुए यहाँ तक कह दिया गया

कि ये बिल्डिंग बीजेपी वाले की आग लग गई तो हम क्या करें? 27 लोगों की 43 लोगों की जान जाने के बाद कह दिया एनओसी एमसीडी ने दी है एमसीडी जिम्मेदार हैं हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ उसके बीच एक 1 साल के अल्पकाल में बजट हमारा हम 20 फरवरी को सरकार में आए थे। मार्च में हमने बजट प्रस्तुत कर दिया था उसके बाद से सधे हुए प्रशासनिक कदमों से क्योंकि अध्यक्ष जी, चीजों में सुधार Populist measure से नहीं आ सकता है, चीजों में सुधार बड़ी-बड़ी घोषणाओं से, अखबारों में विज्ञापन से नहीं, दीर्घकालिक प्रशासनिक उपायों से आता है और जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ दिल्ली फायर सर्विस ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में National Centre for Good Governance के साथ परामर्श कल फायर सर्विस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है, फायर सर्विस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है।

दूसरा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के रिन्यूअल को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है, जिससे ट्रान्सपैरेंसी बड़े, भ्रष्टाचार खत्म हो और एफिशिएंसी बढ़े। इंस्पेक्शन सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। डीरेग्युलेशन के अंतर्गत ऐसे सब बंधक प्रावधानों को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार कम करती जा रही है ताकि दिल्ली की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा राहत दे सकें। 50 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स तैनात किए जा चूके हैं और 50 बहुत जल्दी तैनात हो जाएंगे। आप सब सदस्यों के माध्यम से अध्यक्ष जी आप के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ। सरकार बनते ही पहले फायर सर्विस के रिव्यु में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिव्यु करते समय इस बात की गंभीरता को समझा कि छोटी गलियों में, छोटी गलियों में फायर इंजन जाने में कठिनाई आती है तो छोटी गाड़ियां हायर करके उन गली-मोहल्लों में चिन्हित स्थानों पर खड़ा किया जाए जहाँ से किसी दुर्घटना की संभावना में तुरंत वो वहाँ जा सकें वो ओपन एरिया में उन कॉलोनियों के बाहर खड़ी होंगी, 50 तैनात कर दी जा चुकी है 50 पिछले साल के बजट की अभी तैनात होनी है। आने वाले समय में हमने, हमारे विभाग ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष आने वाली रिक्वायरमेंट बजट के लिए प्रस्तुत की है और सरकार अपने सीमित साधनों में से मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि उन सीमित साधनों में भी दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए सरकार आने वाले समय में भी बजट में भी बड़े कदम उठाने वाली है। वायर मैंने आप सबको बताया वायरलेस नेटवर्क खत्म कर दिया गया। वायरलेस नेटवर्क खत्म करने के बाद आज हमारी सरकार ने उस वायरलेस नेटवर्क की revamping के लिए पूरा प्रोसेस

शुरू कर दिया है। यू.एच.एफ. से वी.एच.एफ. पे ट्रांसफर करते हुए 1969 की टेक्नोलॉजी पर चल रहा था जो भी अभी बचा खुचा है, उसको यूएचएफ से वीएचएफ पर लाते हुये नए तरीके से fire की जो internal communication है ज्यादा प्रभावी ढंग से fire fighting के लिए, ज्यादा प्रभावी ढंग से फायर फाइटिंग के लिए हम उस प्रकार की सुविधा के लिए सरकार ने आगे कर दिया है, काम को बढ़ाया है और एक अत्याधुनिक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। एक ऐसा कमांड सेंटर दिल्ली में कहाँ से कहाँ-कहाँ दुर्घटना घटी है, हमारा फायर इंजन कहाँ है हमारा फायर, फायरमैन कहाँ है, कौन सी मंजिल पर काम कर रहा है कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ ऐसी सब अपने कमांड सेंटर में बैठकर कंट्रोल करके मॉडर्नाइज इक्विपमेंट के साथ, मॉडर्नाइज इक्विपमेंट के साथ एक नए कमांड सेंटर को सरकार बहुत जल्दी स्थापित करने जा रही है और अभी इस घटना के बाद मैंने आपके समक्ष रखा, पिछली सरकार ने इस इस पूरे घटनाक्रम पूरी आग के मामले में केवल एक 2019 की कमेटी बनी। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अभी एक मैजिस्टीरियल इन्क्वाइरी की है और हमने इस बात की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली के फायर सेफ्टी रूल्स रेजिडेंशल इलाकों में लागू नहीं है। हमने उसके संदर्भ में भी एक थर्ड पार्टी ऑडिट दिल्ली की हर एस्टैब्लिशमेंट का हमने उसका आरएफपी फ्लोट कर दिया है तुरंत प्रभाव से एक थर्ड पार्टी दिल्ली सरकार की फायर विभाग के पास अपने सीमित साधन हैं। एक थर्ड पार्टी के साथ residential- cum में होने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कम से कम जब तक कानूनों में परिवर्तन नहीं होगा, उनको हम एडवाइजरी और सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। एक बड़ा प्रयास, भागीरथी प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड करने जा रही है और अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपने कहा, ये सामने के बेंच पर बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी को यहाँ देखते और यहाँ बैठकर हमारे साथ डेलीब्रेट करते दिल्ली की सुरक्षा के लिए, मगर उन्होंने बाहर रहकर बाहर रह कर, अपनी आदत के अनुसार below the belt टुच्ची हरकतें करने का काम किया है टुच्ची हरकतें करने का, अपनी बातों का जवाब न देना पड़े तो अपने ट्वीट में और अपनी दूसरी वार्तालाप में वे लोग मुख्यमंत्री जी के बारे में निजी वल्गर टिप्पणियां करते हैं, निजी और वल्गर टिप्पणियां करते हैं क्यों? क्योंकि अपनी जमीन खो चूके हैं। 1 हजार लोग इकट्ठे नहीं होते उनके पास कि वो किसी मुद्दें पर प्रदर्शन करें तो ये गालियां दे देकर सोशल मीडिया पर traction लेने का काम करते हैं और अध्यक्ष जी नाटक करते हैं कि हमने पूरी पूरा विपक्ष कफ़न बांध लिया हमने सर पर कफन बांध लिया, अरे 11 साल मिले थे अगर सेवा करने के लिए कमर कस लेते हैं तो आज नाटक करने के लिए सर पर कफन ना मानना पड़ता। अगर कमर कस के जनता की सेवा करते, अगर कमर कस के जनता की सेवा में

खड़े रहते तो ये सिर पर कफन बांधने का नाटक ना करना पड़ता। मैं आज इस मंच से एक जिम्मेदार सरकार का जिम्मेदार औहदेदार होने के नाते अध्यक्ष जी आप के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव एप्रोच के साथ हमने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। हमने राजनीति पर राजनीतिक रोटी सेंकने का काम नहीं किया है। passing the buck करने का काम नहीं किया है घृणित टिप्पणी कि मृतक आदमी बीजेपी का नेता था या फलाने दल का नेता था, इसलिए इनके घर आग लगी, ऐसी घृणिक टिप्पणी करने का हमने काम नहीं किया है। कुलदीप जी वहाँ पूरा 3 दिन तक मृतक परिवार के साथ एक विधायक के नाते नहीं, पड़ोसी के नाते, मोहल्ले के नाते, बच्चे के नाते, मैं भी वहाँ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मंत्री के नाते और पड़ोसी के नाते हमने पूरी जिम्मेदारी से उनके साथ खड़े होकर काम किया है और मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार modernization of the fire service and not only to fight against the fire but for the preventive measures to avoid fire accidents उस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। प्रशासनिक उपायों से जो काम होते हैं वो थोड़ा दीर्घकालीन समय लेते हैं। मैं जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ इस सदन के माध्यम से इस पवित्र सदन में जब मैं खड़े होकर ये बयान आपके सामने कर रहा हूँ तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ कि अगले साल डेढ़ साल में बहुत बड़ा परिवर्तन फायर और सेफ्टी के फायर सेफ्टी के मामले में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार देख पाए जनता देख पाएगी, आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया। विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये को एक्सपोज़ करने का समय दिया। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अरविंदर सिंह लवली: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और मुख्यमंत्री जी पर्सनली इंटरेस्ट ले रही है इसमें और निश्चित रूप से 11 साल में अगर ध्यान दिया होता तो इस तरीके के फायर इंसिडेंट नहीं होते तो मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलते हुए केवल एक सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड आ जायेगा इसलिए भी कहना चाहता हूँ। बहुत सारी दिल्ली के अंदर ऐसी कमर्शियल मार्केट्स हैं जो pedestrian commercial है सदर बाजार है, चांदनी चौक है, नई सड़क है, गाँधी नगर है। ये ऐसी शाहदरा में फर्श बजार है तो ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं, जिनके अंदर चार से पांच फिट की रोडस हैं, जिसके ऊपर कमर्शियल एरिया है। वहाँ पर किसी भी कीमत के ऊपर जो है फायर ब्रिगेड का अंदर जाना पॉसिबल नहीं है और एक कॉम्प्रेहेन्सिव प्लान बना था उसको इम्प्लिमेंट

करना चाहिए कि इन मार्केट्स विशेष में एक लाइन पानी की डाल के छोड़नी चाहिए ताकि वो पानी की लाइन तभी ऑपरेट हो इन केस ऑफ फायर तो इसको लेकर जो है सरकार को एक योजना बनानी चाहिए कि ये सारी मार्केट्स को कवर करना चाहिए, जिसके अंदर फायर ब्रिगेड ही नहीं जा सकती। भगवान ना करे वहाँ पे कोई हादसा हो गया तो गाडी जा नहीं पायेगी, पानी बुझाने का कोई साधन नहीं है, पाइप इतनी लंबी है नहीं तो इसके लिए एक विस्तृत योजना योजना जो है वो सरकार को ये फायर डिपार्ट्मेन्ट को बनानी चाहिए कि कभी भी गलती से ऐसा हादसा हो जाए तो उसके लिए सरकार प्रपेयर रहे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री कार्यसूची के बिंदु क्रमांक छः के उप बिंदु एक में दर्शाए गए दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

श्रीमती रेखा गुप्ता(माननीय मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक छः के उप बिंदु एक में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं।

6. 1. सदन पटल पर प्रस्तुत किये गए कागजात:

I. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2021को समाप्त हुए वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित, राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 01)[7]

II. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2020 एवं 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित, राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 03)[8]

III. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 01)[9]

IV. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित, राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 02)[10]

---

[7] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23550 पर उपलब्ध।

[8] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23551 पर उपलब्ध।

[9] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23552 पर उपलब्ध।

[10] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23553 पर उपलब्ध।

V. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित, राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 02)[11]

VI. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 05)[12]

VII. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित, दिल्ली जल बोर्ड की कार्य प्रणाली प्रतिवेदन (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 03)[13]

VIII. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विश्वविधालयों की कार्य प्रणाली पर प्रतिवेदन (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 04)[14]

IX. दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2025 के संदर्भ में जारी अधिसूचना संख्या एफआईएन-एसआरडी016/2/2025- एसआरडी-वित्त विभाग, दिनांक 22 दिसंबर, 2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति) [15]

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सभी सदस्यों को ये प्रतियाँ सर्कुलेट कर दी जाए। अब श्री आशीष सूद, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री कार्यसूची के बिंदु क्रमांक छ: के उप बिंदु दो में दर्शाए गए दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

श्री आशीष सूद, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 06 के उप बिंदु दो में दर्शाए गए दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

6. (II)

I. वित्त वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 हेतु इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आईआईआईटीडी) के वार्षिक लेखों साहित सीएजी का प्रथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और एसएआर पर कार्रवाई रिपोर्ट (अंग्रेजी प्रति) तथा वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)। [16]

II. समापन वर्ष 31.03.2011, 31.03.2012, 31.03.2013 एवं 31.03.2014 के लिए दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)। [17]

---

[11] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23554 पर उपलब्ध।

[12] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23555 पर उपलब्ध।

[13] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23556 पर उपलब्ध।

[14] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23557 पर उपलब्ध।

[15] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23558 पर उपलब्ध।

[16] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23559 पर उपलब्ध।

[17] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23560 पर उपलब्ध।

III. वित्त वर्ष 2022-23 हेतु डॉ0 भीम रॉव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के वार्षिक लेखा और पृथक लेखा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)।[18]

IV. दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) नियमावली, 2025 के संदर्भ में जारी अधिसूचना संख्या फा.सं. डी0ई0 15(375)/पीएसबी/2025/9516-9524 दिनांक 09 दिसंबर, 2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)।[19]

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात- तीन। अब श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कार्यसूची के बिंदु क्रमांक छः के उपबिंदु तीन में दर्शाए गए दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिदुं क्रमांक छः के उप बिंदु तीन में दर्शाए गए दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

6.(III)

दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2025 के संदर्भ में जारी अधिसूचना संख्या फा.सं.12(2)/डब्ल्यू&एम/ प्रवर्तन/2023/10061-69 बांट एवं माप विभाग (विधि माप विज्ञान विभाग दिनांक 27 जनवरी, 2026 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)[20]

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जो भी माननीय सदस्यगण जो भी सदन पटल पर रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएजी की रिपोर्टस रखी गई है और ये वो रिपोर्ट्स हैं जिनमें मोहल्ला क्लिनिक के संदर्भ में सीएजी रिपोर्ट है। जो शीशमहल की बात जो बार बार उठती है, उस पर सीएजी की जो रिपोर्ट है वो उसमें दर्शाई गई है और इसी प्रकार के और भी स्कूल के कमरों के निर्माण आदि को लेकर के, तो इन सब को के बारे में विषय में पर 25 तारीख को समय तय कर के और आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद सदन इन तमाम रिपोर्टस पर फैसला लेगा और आगे की कार्रवाई के लिए इनको भेजेगा। इसी तरह आज जो माननीय अध्यक्ष, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी द्वारा भी जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो प्रिविलेज कमिटी के अध्यक्ष द्वारा भी जो माननीय अध्यक्ष द्वारा भी जो रिपोर्ट पेश की गई है फांसी घर पर, इस पर भी हम 25 तारीख और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर उसको देखेंगे। लेकिन चर्चा के लिए सदन के समक्ष लाएंगे। अब सदन की कार्यवाही दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कल 11:00 बजे माननीय मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करेंगी, इसलिए सभी सदस्यों से अनुरोध है कि समय से अपना स्थान ले लें। धन्यवाद।

---

[18] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23561 पर उपलब्ध।

[19] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23562 पर उपलब्ध।

[20] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23563 पर उपलब्ध।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)